'यूपी राइज 2026' : कैंपस से उठी बदलाव की नई आवाज

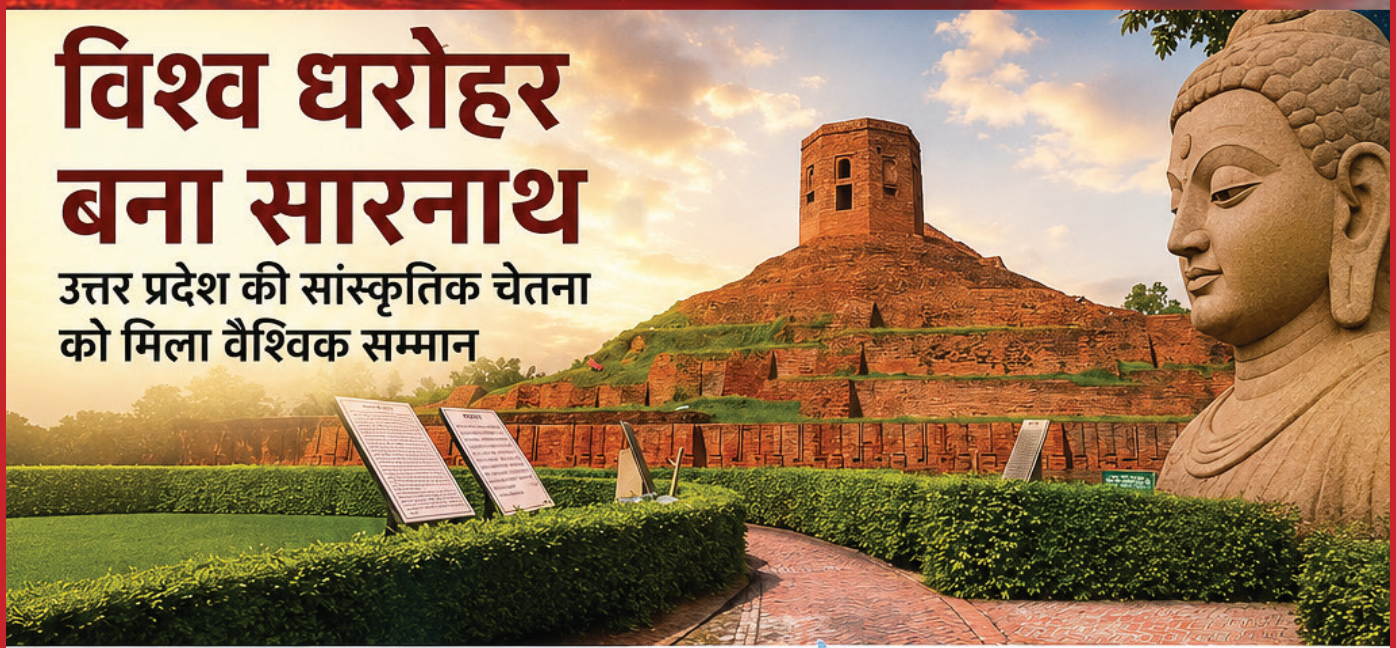
हरियाणा की टेली-ईसीजी सेवा: 'गोल्डन ऑवर' में जीवन बचाने का नया भरोसा

स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली की ओर ऐतिहासिक कदम

RNI No.: UPHIN/2018/76675
वर्ष 7 | अंक 8 | अगस्त 2026 | ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका



विश्व धरोहर बना सारनाथ

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को मिला वैश्विक सम्मान



'यूपी राइज 2026'

कैंपस से उठी बदलाव की नई आवाज़



हरियाणा की टेली-ईसीजी सेवाः

'गोल्डन आवर' में जीवन बचाने का नया भरोसा



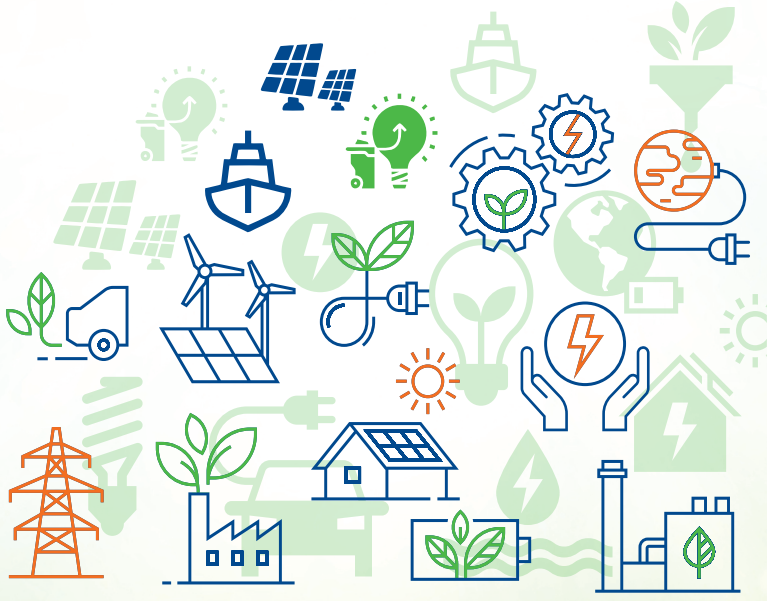
भारत की नई डिजिटल उड़ान

(एक महारत्न कंपनी)

राष्ट्र की सशक्त संधारणीय संवृद्धि की ओर अग्रसर

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता

62,000 मेगावाट – समर्थित हरित ऊर्जा क्षमता संवर्धन



उत्पाद एवं सेवाएं

- परियोजना सावधि ऋण
- ऋण पुनर्वित्तपोषण
- नवीकरणीय ऊर्जा/ ई-मोबिलिटी
- अवशिष्ट से ऊर्जा
- रिफाइनरी
- बंदरगाह

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

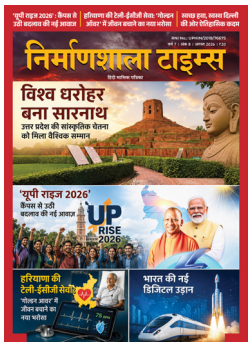
(एक महारत्न कंपनी)

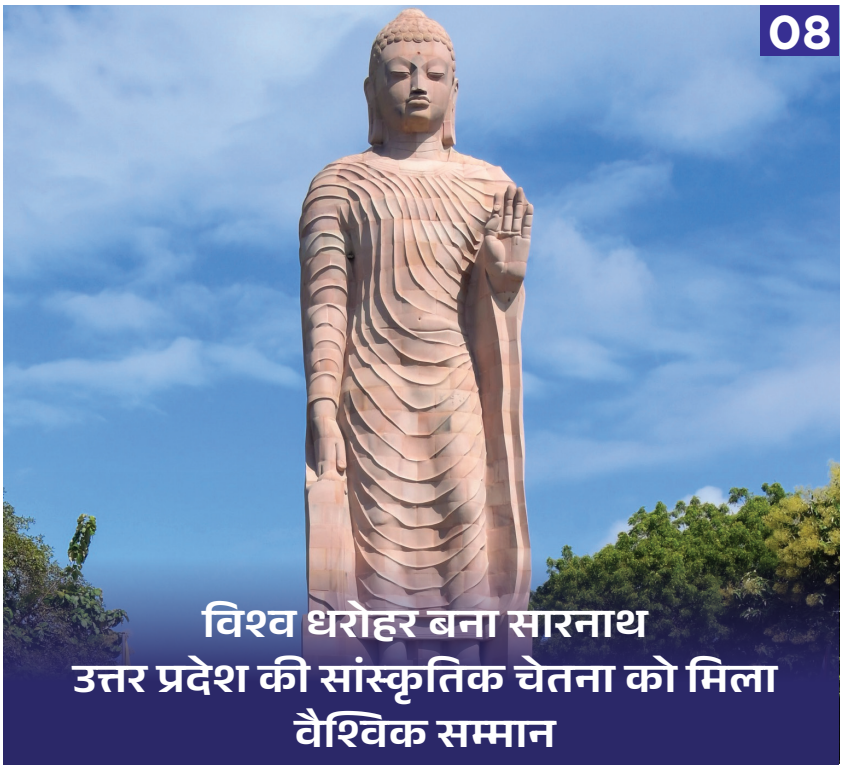
www.pfcindia.com

उज्ज्वल भविष्य के लिए वित्तपोषण

/pfclindia | /pfclindia | /pfclindia

इस अंक में







'यूपी राइज 2026' : कैंपस से उठी बदलाव की नई आवाज



SHE-LEAPS : डिजिटल सशक्तिकरण से 'लखपति दीदी' तक—ग्रामीण भारत की नई उड़ान



हरियाणा की टेली-ईसीजी सेवा: 'गोल्डन ऑवर' में जीवन बचाने का नया भरोसा



वेलमैन फाउंडेशन: सेवा, संस्कार और स्वावलंबन का सशक्त अभियान

निर्माणशाला टाइम्स
हिंदी मासिक पत्रिका
मूल्यः 20 रुपये, अगस्त 2026
वर्ष-7 अंकः 8, पृष्ठः 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह
संपादक
अहमद हसन
सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com
E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com
Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तर प्रदेश-	**सी.बी. सिंह**
उत्तराखंड-	**विनय त्रिवाल**
दिल्ली-	**दिनेश कुमार सिंह**
बिहार-	**सैयद मोहम्मद अली**
हरियाणा-	**संतोष कुमार सिंह**
झारखंड-	**परवेज कमाल**
डिजाइन-	**चंद्रजीत कुमार**

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार
NST MEDIA
WP-02, Block 'C'
Sector - 71, Noida - 201301
Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय
मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।

पत्र का नाम-
निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times)
RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

गौतम बुद्ध नगर

नए भारत की आर्थिक शक्ति, उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का प्रवेश द्वार

उत्तर प्रदेश आज परिवर्तन के उस दौर से गुजर रहा है, जहाँ विकास केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाली वास्तविक उपलब्धि बन चुका है। इस परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली तस्वीर यदि कहीं दिखाई देती है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर —एक ऐसा जनपद जिसने कुछ ही वर्षों में स्वयं को देश के सबसे गतिशील औद्योगिक, तकनीकी और निवेश केंद्रों में स्थापित कर लिया है।

आज गौतम बुद्ध नगर केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की नई आर्थिक ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, अत्याधुनिक औद्योगिक कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डेटा सेंटर, स्टार्टअप संस्कृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक शिक्षा संस्थान और प्रस्तावित जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा—ये सभी मिलकर इस जनपद को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं।

विकास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गाँवों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्यमियों तक भी पहुँचे। गौतम बुद्ध नगर इसी समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, डिजिटल सेवाओं का प्रसार, कौशल विकास तथा स्वरोजगार के नए अवसर इस परिवर्तन को जन-जन तक पहुँचा रहे हैं।

आर्थिक प्रगति का वास्तविक अर्थ तभी है जब उसके केंद्र में आम नागरिक हो। यही कारण है कि आज पारदर्शिता, सुशासन, तकनीक आधारित प्रशासन और जनभागीदारी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। निवेश के साथ विश्वास और विकास के साथ उत्तरदायित्व का यह संतुलन ही गौतम बुद्ध नगर को विशिष्ट बनाता है।

"**निर्माणशाला टाइम्स**" का यह विश्वास है कि सकारात्मक सोच, रचनात्मक संवाद और विकास की प्रेरक कहानियाँ समाज में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। हमारा उद्देश्य केवल उपलब्धियों का वर्णन करना नहीं, बल्कि उन प्रयासों को सामने लाना है जो भविष्य के भारत की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।

गौतम बुद्ध नगर आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का इंजन बनकर उभर रहा है। यदि यही गति, यही दूरदृष्टि और यही जनकेंद्रित विकास मॉडल निरंतर आगे बढ़ता रहा, तो वह समय दूर नहीं जब यह जनपद केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की आर्थिक प्रगति का अग्रदूत और वैश्विक निवेश का सबसे विश्वसनीय केंद्र बनकर स्थापित होगा।

विकास की यह यात्रा केवल सरकार या उद्योग की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। आइए, हम सब मिलकर ऐसे गौतम बुद्ध नगर के निर्माण में सहभागी बनें, जो समृद्धि, नवाचार, रोजगार, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सबसे उज्ज्वल प्रतीक बने।

यीडा की 91वीं बोर्ड बैठक: निवेश, उद्योग और विकास की नई उड़ान

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र बना उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का सबसे मजबूत इंजन



निर्माणशाला टाइम्स

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 91वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश को औद्योगिक, निवेश, रोजगार और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले साबित होंगे। बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन, किसानों के हित, अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और विश्वस्तरीय शहरी विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर हैं।

राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि, विकास कार्यों को मिली नई गति

प्राधिकरण ने वित्तीय अनुशासन और प्रभावी कार्यशैली का परिचय देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में **1,371.75 करोड़ रुपये** की आय अर्जित की, जो पिछले वर्ष की तुलना में **114 प्रतिशत से अधिक वृद्धि** दर्शाती है। औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि योजनाओं से प्राप्त राजस्व ने निवेशकों के बढ़ते विश्वास को भी प्रमाणित किया है।

औद्योगिक पार्क बन रहे रोजगार के नए केंद्र

एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, अपैरल पार्क तथा मेडिकल डिवाइस पार्क में तेज़ी से कार्य आगे बढ़ रहा है। एक माह में 63 लीज डीड, 118 भूखंडों का कब्जा, 84 निर्माण कार्य प्रारंभ तथा 15 उद्योगों का उत्पादन शुरू होना इस बात का संकेत है कि यीडा क्षेत्र तेजी से उत्पादन और रोजगार का नया हब बन रहा है।

यीडा की 91वीं बोर्ड बैठक के निर्णय केवल प्रशासनिक मंजूरियां नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का रोडमैप हैं। निवेश, रोजगार, अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और किसान हितों के समन्वय के साथ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को नई गति प्रदान कर रहा है।

विश्वस्तरीय व्यापार केंद्र की ओर कदम

यीडा क्षेत्र में **Yeida International Trade City** विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात और वैश्विक निवेश को नई गति प्रदान करेगी तथा उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बनेगा विशाल इंडस्ट्रियल नोड

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र में विशाल **Industrial Node** विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे एयरपोर्ट आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और निर्यात गतिविधियों को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

अनुसंधान एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात

सेक्टर-9 में **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)** को 30 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे अत्याधुनिक शोध सुविधाएं विकसित होंगी और उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेगा।

किसानों के हित सर्वोपरि

अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर



यीडा क्षेत्र में Yeida International Trade City विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात और वैश्विक निवेश को नई गति प्रदान करेगी तथा उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाएगी।

तथा **7 प्रतिशत आबादी भूखंड** के शीघ्र आवंटन के निर्देश किसानों के हितों के प्रति सरकार और प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इससे विकास और किसान हितों के बीच संतुलन मजबूत होगा।



हरित विकास और सुरक्षित भविष्य

उच्च भवनों में अग्नि सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित शहरी विकास के प्रति यीडा की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं।

हरित परिवहन को बढ़ावा

एनटीपीसी द्वारा संचालित **इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बसों** के संचालन की समीक्षा करते हुए आमजन को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। यह स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य के आधुनिक शहर की मजबूत नींव

नई होटल नीति, मास्टर प्लान सड़कों, विद्युत अवसंरचना, औद्योगिक सेक्टरों के विस्तार तथा लंबित रियल एस्टेट परियोजनाओं के समाधान संबंधी निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि यीडा क्षेत्र केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विश्वस्तरीय, आधुनिक और सुव्यवस्थित स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। ■

युवा बने विकास यात्रा के सारथी

'यूपी राइज 2026' : कैंपस से उठी बदलाव की नई आवाज



उत्तर प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को नई पहचान देने के उद्देश्य से आयोजित **'यूपी राइज 2026 : संवाद, संकल्प, सफलता'** कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रदेश का युवा विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं टाइम्स नाऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वयं को **'कैंपस ब्रांड एम्बेसडर'** के रूप में समाज और सरकार के बीच सकारात्मक संवाद का माध्यम बनाने का संकल्प लिया।



कार्यक्रम में युवाओं ने एक स्वर में कहा कि उत्तर प्रदेश आज शिक्षा, निवेश, उद्योग, स्टार्टअप, कौशल विकास और स्वरोजगार के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। बदलती कार्यसंस्कृति, बेहतर आधारभूत सुविधाएँ और बढ़ते निवेश ने प्रदेश को युवाओं के लिए अवसरों की नई भूमि बना दिया है। यही कारण है कि अब प्रदेश का युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने ही राज्य को सबसे उपयुक्त मंच मान रहा है।

डिजिटल युग में युवा बने परिवर्तन के दूत

सोशल मीडिया आज केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जनजागरण और सकारात्मक बदलाव का सशक्त मंच बन चुका है। कार्यक्रम में शामिल युवा कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स ने संकल्प लिया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रेरक कहानियों और विकास कार्यों की प्रमाणिक जानकारी समाज तक पहुँचाकर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की यह भागीदारी सुशासन और जनसहभागिता का नया अध्याय लिख रही है।

संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानियाँ

कार्यक्रम में अनेक छात्र-छात्राओं ने अपने जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को साझा किया। इन अनुभवों ने यह संदेश दिया कि आत्मविश्वास, मेहनत और सही अवसर मिलने पर कोई भी चुनौती सफलता की राह नहीं रोक सकती। इन प्रेरक कहानियों ने उपस्थित युवाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया।

महिला सशक्तिकरण बना विकास का आधार

कार्यक्रम में मिशन शक्ति, स्वयं सहायता समूह, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी पहलों पर विशेष चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने माना कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दे रही है। ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वरोजगार की दिशा में हुए प्रयास प्रदेश के समावेशी विकास की सशक्त पहचान बन चुके हैं।

"आज का युवा केवल अवसर नहीं तलाश रहा, बल्कि अवसरों का निर्माण करने और समाज को नई दिशा देने का संकल्प भी ले रहा है।"

नई सोच, नया संकल्प

'यूपी राइज 2026' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों, संकल्पों और नेतृत्व क्षमता का उत्सव है। जब विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएँ विकास की कहानी के सहभागी बनते हैं, तब परिवर्तन केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की सोच का हिस्सा बन जाता है।

युवा शक्ति, सकारात्मक सोच और जनभागीदारी ही विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूँजी है। यही ऊर्जा प्रदेश को प्रगति, नवाचार और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ■

विशेष आवरण कथा

विश्व धरोहर बना सारनाथ

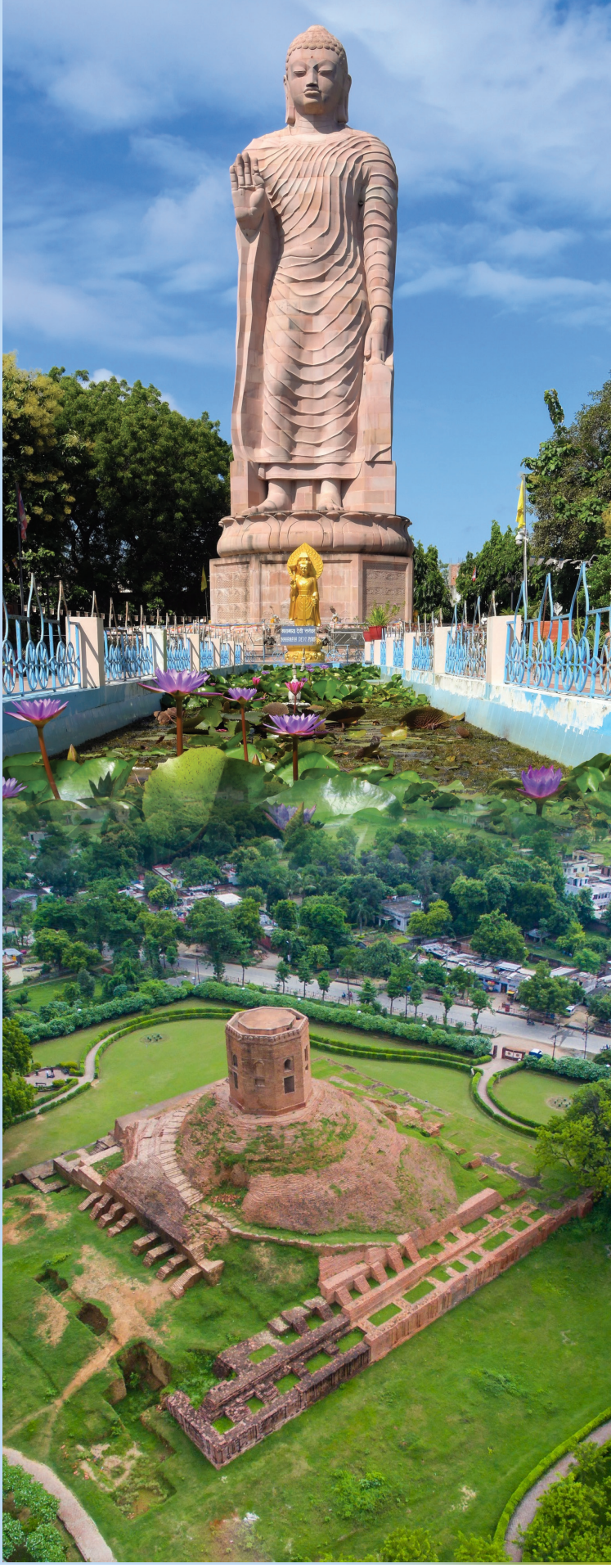
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को मिला वैश्विक सम्मान

"जहाँ से चला था धर्मचक्र, वहीं से अब विश्व को मिलेगा भारतीय संस्कृति और शांति का नया संदेश।"



सी.बी. सिंह
ब्यूरो प्रमुख (उत्तर प्रदेश)

लगभग अट्ठाईस वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश की पावन बौद्ध स्थली **सारनाथ** को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही



सारनाथ भारत का 45वाँ तथा उत्तर प्रदेश का **चौथा विश्व धरोहर स्थल** बन गया।

यह उपलब्धि केवल एक ऐतिहासिक स्मारक को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और उत्तर प्रदेश की समृद्ध सभ्यता के वैश्विक सम्मान का प्रतीक भी है। **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ** के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास की दिशा में किए गए सतत प्रयासों का यह एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।

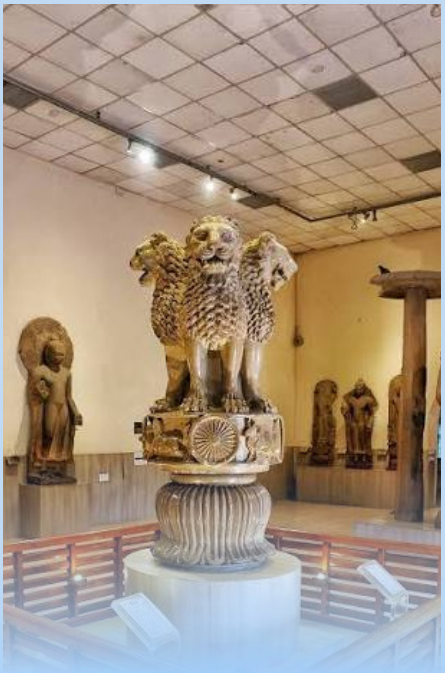
सारनाथ : जहाँ मानवता ने सुना था करुणा का पहला संदेश

वाराणसी से कुछ ही दूरी पर स्थित सारनाथ वह पावन भूमि है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपना प्रथम उपदेश देकर **धर्मचक्र प्रवर्तन** का शुभारंभ किया था। यहीं से करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और विश्व बंधुत्व का संदेश सम्पूर्ण मानवता तक पहुँचा।

प्राचीन ग्रंथों में इसे **ऋषिपत्तन** तथा **मृगदाय** के नाम से भी वर्णित किया गया है। लगभग 2600 वर्षों से यह स्थल बौद्ध श्रद्धालुओं, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है।

विश्व धरोहर का गौरव : इतिहास से भविष्य तक

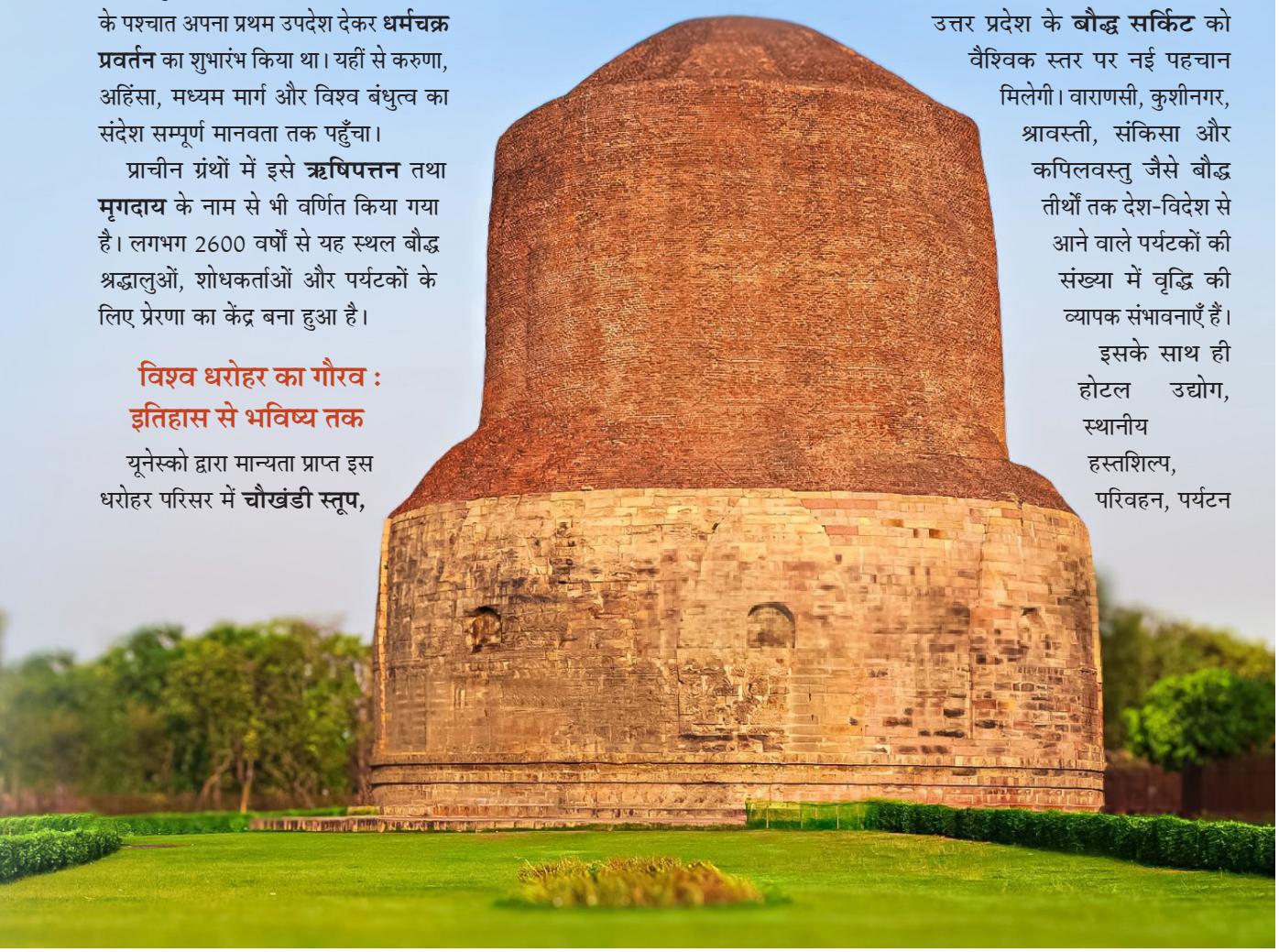
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस धरोहर परिसर में **चौखंडी स्तूप, धामेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, अशोक स्तंभ** तथा **प्राचीन विहारों के अवशेष** शामिल हैं। ये स्मारक न केवल बौद्ध स्थापत्य कला की उत्कृष्ट मिसाल हैं, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि के जीवंत प्रमाण भी हैं।



सारनाथ को वर्ष 1998 में यूनेस्को की संभावित सूची (Tentative List) में शामिल किया गया था। लगभग तीन दशक बाद मिली यह मान्यता धैर्य, संरक्षण और सुविचारित प्रयासों की सफलता का प्रतीक है।

पर्यटन और विकास को मिलेगा नया आयाम

विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से उत्तर प्रदेश के **बौद्ध सर्किट** को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा और कपिलवस्तु जैसे बौद्ध तीर्थों तक देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की व्यापक संभावनाएँ हैं। इसके साथ ही होटल उद्योग, स्थानीय हस्तशिल्प, परिवहन, पर्यटन





सेवाओं तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार से पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

विरासत संरक्षण की नई सोच

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण, आधुनिक सुविधाओं के विकास और वैश्विक प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया है। बौद्ध देशों के प्रतिनिधिमंडलों, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों, फैम ट्रिप और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की विरासत को विश्व मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

सारनाथ को मिली यह मान्यता इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो भविष्य में प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

भारत की आध्यात्मिक विरासत का विश्व संदेश

आज जब विश्व शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस कर रहा है, ऐसे समय में सारनाथ की यह उपलब्धि भारत के आध्यात्मिक दर्शन को नई वैश्विक पहचान प्रदान करती है।

"सारनाथ केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान, करुणा और विश्व शांति का अमर प्रतीक है। इसकी वैश्विक पहचान सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए गर्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।"

भगवान बुद्ध का संदेश केवल किसी एक धर्म का संदेश नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए करुणा, समरसता और शांति का मार्ग है। यूनेस्को की यह मान्यता उस शाश्वत संदेश को और अधिक व्यापक स्वर प्रदान करेगी।

ब्यूरो प्रमुख दृष्टि

सारनाथ का विश्व धरोहर बनना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक यात्रा का स्वर्णिम अध्याय है। यह उपलब्धि बताती है कि जब विरासत संरक्षण को विकास की धारा से जोड़ा जाता है, तब इतिहास केवल संग्रहालयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों का मार्गदर्शक बन जाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस गौरवशाली धरोहर के संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता, पर्यावरण, स्थानीय सहभागिता और सांस्कृतिक जागरूकता को भी जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। तभी सारनाथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी गरिमा और भव्यता के साथ सुरक्षित रह सकेगा।

विशेष तथ्य

- भारत का 45वाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
- उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल
- लगभग 28 वर्षों बाद मिला विश्व धरोहर का दर्जा
- भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मदेशना की पावन भूमि
- बौद्ध सर्किट को मिलेगा वैश्विक पर्यटन का नया आयाम ■

सूर्य से समृद्धि तक

पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश ने रचा नया इतिहास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बना देश का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू रूफटॉप सोलर राज्य

स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत और हरित विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** के नेतृत्व में प्रधानमंत्री **सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** के प्रभावी क्रियान्वयन ने प्रदेश को घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि केवल एक सरकारी योजना की सफलता नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।

हर छत बनी ऊर्जा का स्रोत, हर परिवार बना आत्मनिर्भर

प्रदेश में अब तक **6.74 लाख से अधिक घरेलू रूफटॉप सोलर** संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता प्रदेश सरकार की प्रभावी मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और मिशन मोड में किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

2.28 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा: ऊर्जा क्रांति की नई पहचान

यूपी नेडा के निदेशक **रविन्दर सिंह** के अनुसार प्रदेश में अब तक **2,283.8 मेगावाट** घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित हो चुकी है। लाखों परिवार अब अपनी छतों पर स्वयं बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता



ऊर्जा उत्पादक की भूमिका भी निभा रहे हैं।

सोलर इकोनॉमी बनी रोजगार का नया इंजन

पीएम सूर्य घर योजना ने उत्तर प्रदेश में **7,000 से अधिक कंपनियों** और व्यावसायिक इकाइयों को नई गति दी है। इसके माध्यम से **85,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार** सृजित हुए हैं। इंस्टॉलेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कार्य, नेट मीटरिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय उद्यमियों के लिए नए अवसर विकसित हुए हैं।

"हर छत पर सोलर, हर घर में समृद्धि — यही है नए उत्तर प्रदेश की हरित विकास गाथा।"

औद्योगिक विकास को मिली हरित ऊर्जा की ताकत

रूफटॉप सोलर की बढ़ती मांग ने प्रदेश में सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबल और अन्य उपकरणों के निर्माण एवं असेंबली उद्योग को नई गति प्रदान की है। इससे एमएसएमई, स्थानीय उद्योगों और निवेश को बढ़ावा मिला है तथा उत्तर प्रदेश में ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है।

पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी मॉडल

घरेलू रूफटॉप सोलर के विस्तार से अनुमानित **9,000 एकड़ से अधिक भूमि** की बचत हुई है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए अलग भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ ही प्रतिवर्ष लगभग **3.8 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली** का उत्पादन संभव हुआ है, जिससे **27 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** में कमी आने का अनुमान है। यह पर्यावरण संरक्षण और भारत के नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।

नई ऊर्जा, नया उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इसे आर्थिक विकास, रोजगार, औद्योगिक निवेश और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम बना रहा है। **पीएम सूर्य घर योजना** आज प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य का आधार बन चुकी है। ■

'ग्रामोदय से राष्ट्रोदय' की दिशा में बिहार की प्रभावी दस्तक



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में जियो-टैगिंग मॉडल की सराहना, ग्रामीण विकास के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता हुई और मजबूत

विकसित भारत–2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में गांवों की भूमिका को केंद्र में रखते हुए आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बिहार ने अपनी नवाचारपूर्ण पहल और प्रभावी कार्यशैली से विशेष पहचान बनाई। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री **श्री श्रवण कुमार** ने सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा किए।

'ग्रामोदय से राष्ट्रोदय' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने ग्रामीण समृद्धि, सशक्त पंचायत व्यवस्था, आजीविका संवर्धन और आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** ने विकसित भारत के लक्ष्य में गांवों की निर्णायक भूमिका पर बल दिया।

सम्मेलन का सबसे सकारात्मक पक्ष यह रहा कि **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अंतर्गत बिहार की **ऑन-साइट जियो-टैगिंग** पहल को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं (Best Practices) में शामिल करते हुए सराहा गया। इस तकनीकी नवाचार ने आवास निर्माण की निगरानी को अधिक पारदर्शी, सटीक और जवाबदेह बनाया है, जो सुशासन की दिशा में बिहार के प्रयासों का सशक्त उदाहरण है।

अपने संबोधन में मंत्री श्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया है। साथ ही वर्ष 2015 से पूर्व निर्मित जर्जर मकानों के मरम्मत एवं उन्नयन की आवश्यकता पर भी गंभीरता से ध्यान आकर्षित किया, जिससे ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। ग्रामीण आजीविका, आधारभूत सुविधाओं, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी को सुदृढ़ करते हुए राज्य सरकार आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार की सक्रिय एवं सार्थक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि राज्य नवाचार, पारदर्शिता और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास की नई इबारत लिख रहा है। विकसित भारत के निर्माण का मार्ग विकसित गांवों से होकर गुजरता है, और इस दिशा में बिहार की पहल देश के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है। ■



हरियाणा विजन@2047 : हर जिले में स्टार्टअप, हर हाथ को रोजगार

उद्योग, नवाचार और कौशल विकास के नए युग की ओर बढ़ता हरियाणा



हरियाणा विजन@2047 केवल भविष्य की परिकल्पना नहीं, बल्कि उद्योग, नवाचार, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और हरित अर्थव्यवस्था को साथ लेकर आगे बढ़ने की व्यापक कार्ययोजना है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, स्थानीय उद्योगों का विस्तार, ग्रामीण कौशल विकास और निवेश-अनुकूल वातावरण जैसी पहलें हरियाणा को रोजगार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगी।

'हर जिले में स्टार्टअप्स का द्वार, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत आधार' —मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की यह सोच केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि हरियाणा विजन@2047 के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का स्पष्ट रोडमैप है। सरकार ने उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, कौशल विकास और महिला उद्यमिता को केंद्र में रखकर प्रदेश को आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित और रोजगार-सृजन करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाया जाए तथा उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।

स्थानीय उद्योगों को मिलेगा नया विस्तार

प्रदेश के बरवाला क्षेत्र में आधुनिक **वुडन जोन एवं वुडन मार्केट** विकसित किए जाएंगे, जहाँ अत्याधुनिक शोरूम स्थापित होंगे। इससे लकड़ी आधारित उद्योगों को नई पहचान मिलेगी, स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ेगी और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। साथ ही प्रत्येक जिले में स्वदेशी मेलों के आयोजन की योजना स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में



महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

स्वयं सहायता समूहों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल

सरकार स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। विशेष रूप से राखी सहित स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

व्यवसाय करना होगा और अधिक आसान

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में **'राज्य नवाचार एवं एमएसएमई परिषद'** तथा **'स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हरियाणा'** का गठन किया जाएगा। पुनर्गठित सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से औद्योगिक स्वीकृतियों का समय 45 दिनों से घटाकर 30 दिन किया जाएगा तथा भविष्य में इसे और कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में नियुक्त **स्टार्टअप संपर्क अधिकारी** नए उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराएंगे।

'पद्मा' योजना से औद्योगिक विकास को नई गति

राज्य सरकार की प्रतिष्ठित **'पद्मा' योजना** के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में **10 नए औद्योगिक क्लस्टर** स्थापित किए जाएंगे। साथ ही स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने के लिए **2,000 करोड़ रुपये का 'हरियाणा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स'** स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले **250 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड** भी प्रारंभ किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास का नया मॉडल

प्रदेश के 100 उच्च क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप **विशेष कौशल केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। हिसार में बीड्स निर्माण, पानीपत में हथकरघा, करनाल में कृषि उपकरण एवं डेयरी तथा यमुनानगर में पॉटरी जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। वहीं आईटीआई संस्थानों में आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे तथा उद्योगों की भागीदारी बढ़ाकर युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हरित उद्योग और सतत विकास पर विशेष जोर

नई औद्योगिक नीति के तहत 2,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सोलर रूफटॉप अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। पानीपत में **10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट** स्थापित किया जा रहा है, जो हरियाणा को हरित औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रणी बनाएगा।

महिला उद्यमिता को मिलेगा नया संबल

महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए **'महिला उद्यमिता मंच'** के तहत 11.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से सैकड़ों महिला उद्यमियों को मेंटरिंग, वित्तीय सहायता और व्यावसायिक मार्गदर्शन मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में **क्रैच (बाल-देखभाल केंद्र)** स्थापित किए जाएंगे, जिससे कार्यरत महिलाओं को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

हरियाणा बनेगा नवाचार और निवेश का प्रमुख केंद्र

कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक को तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क मॉडल पर विकसित कर वैकल्पिक आईटी हब बनाया जाएगा। साथ ही **'मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026'** तथा **'हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति-2026'** के माध्यम से निवेश, निर्यात और औद्योगिक विकास को नई गति दी जाएगी। ■

हरित ऊर्जा की ऐतिहासिक उड़ान

जींद से विकसित भारत के नए युग का शुभारंभ

स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के संगम ने हरियाणा के जींद को देश की हरित विकास यात्रा का नया प्रतीक बना दिया। देश की पहली **हाइड्रोजन ट्रेन** के शुभारंभ और इको-फ्रेंडली रैली ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर है। यह ऐतिहासिक अवसर केवल हरियाणा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए स्वच्छ, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नई शुरुआत का प्रेरक संदेश लेकर आया।



प्रधानमंत्री **श्री नरेंद्र मोदी** की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री **श्री नायब सिंह सैनी** ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और विकसित भारत के शिल्पकार की संज्ञा दी। उन्होंने हरियाणा को **14,721 करोड़** की लागत वाली नौ महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। ये परियोजनाएं प्रदेश में आधारभूत ढांचे, रेलवे, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेंगी।

जींद की इको-फ्रेंडली रैली इस आयोजन का विशेष आकर्षण रही। हजारों नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी ई-व्हीकल तथा ग्रीन एनर्जी आधारित वाहनों के साथ रैली में शामिल हुए। यह केवल एक रैली नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प और जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण थी। इस पहल ने स्पष्ट संदेश दिया कि हरित ऊर्जा को अपनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज देश केवल विकास की बातें नहीं करता, बल्कि दुनिया के सामने विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। रेल, सड़क, एक्सप्रेस-वे, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भारत कभी तकनीक का आयात करता था, आज वही भारत विश्व को आधुनिक तकनीक और नवाचार का मार्ग दिखा रहा है।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हरियाणा से संचालन प्रधानमंत्री के **हरित ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन** और **आत्मनिर्भर भारत** के विजन का सशक्त प्रतीक है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था विकसित करने और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से आगे बढ़कर हरित तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रत्येक 20 किलोमीटर पर कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तथा सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की योजनाएं प्रदेश के समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला बन रही हैं।

जींद का यह ऐतिहासिक आयोजन इस विश्वास को और मजबूत करता है कि भारत का भविष्य हरित ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और जनसहभागिता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलित मॉडल के साथ हरियाणा ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि विकसित भारत-2047 का सपना केवल संकल्प नहीं, बल्कि तेजी से साकार होती हुई वास्तविकता है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव सिद्ध होगी। ■

धरती के नाम हरित संकल्प

35 करोड़ पौधरोपण का महाअभियान: हरित उत्तर प्रदेश की ओर ऐतिहासिक कदम

"एक पेड़, एक संकल्प—मां, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के नाम"



उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ते हुए **एक ही दिन में 35 करोड़ पौधरोपण** के लक्ष्य के साथ व्यापक **पौधरोपण महाअभियान-2026** का सफल आयोजन किया। मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** ने गोरखपुर से इस महाअभियान का शुभारंभ करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि यह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि **धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महायज्ञ है**। प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** के आह्वान "**एक पेड़ मां के नाम**" अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर **नीम, पीपल** और **बरगद** की पवित्र त्रिवेणी का रोपण किया। यह संदेश केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है।

विकास और पर्यावरण का संतुलित मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते नौ वर्षों के दौरान एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ-साथ वनाच्छादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में लगाए गए **242 करोड़ से अधिक पौधों** ने करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करती है।

प्रकृति के प्रति भारतीय संस्कृति का संदेश

मुख्यमंत्री ने अथर्ववेद के मंत्र—
"**माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः**"
का उल्लेख करते हुए कहा कि धरती हमारी माता है और हम सभी उसके पुत्र हैं। इसलिए उसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल आज का कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का निवेश है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती और समाधान

मुख्यमंत्री ने मौसम चक्र में आए परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षा में विलंब, बढ़ती गर्मी, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं प्रकृति के साथ असंतुलित व्यवहार का परिणाम हैं।

उन्होंने कहा कि समाधान केवल सरकारी योजनाओं में नहीं बल्कि जनभागीदारी में है। प्रत्येक नागरिक यदि एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में







पर्यावरणीय संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

हरित उत्तर प्रदेश के लिए बहुआयामी प्रयास

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि एलईडी स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, कार्बन क्रेडिट योजना तथा उज्ज्वला योजना जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम से सतत विकास का व्यापक मॉडल प्रस्तुत किया है।

किसानों को कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक प्रोत्साहन से भी जोड़ा गया है, जिससे हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

गौतम बुद्ध नगर ने भी निभाई हरित उत्तरदायित्व की मिसाल

प्रदेशव्यापी पौधरोपण महाअभियान के क्रम में **जनपद गौतम बुद्ध नगर** ने भी उल्लेखनीय सहभागिता दर्ज कराई। कैबिनेट मंत्री **श्री सुनील कुमार शर्मा** एवं **जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम** के नेतृत्व में जिलेभर में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अवसर पर **नोएडा प्राधिकरण** के अध्यक्ष **श्री दीपक कुमार,** मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री कृष्ण करुणेश, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण** के मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री राकेश कुमार सिंह,** अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री शैलेंद्र कुमार भाटिया** एवं **श्री राजेश कुमार** सहित अनेक अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।



ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जिले के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव **श्री अनिल गर्ग** के मार्गदर्शन में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्रीमती श्रीलक्ष्मी वी.एस.** तथा **श्री सुमित यादव** के नेतृत्व में बड़े स्तर पर पौधरोपण कर हरित विकास के संकल्प को साकार किया गया।

तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों—**नोएडा, ग्रेटर नोएडा** एवं **यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण** —ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं, विद्यालयों, उद्योगों तथा नागरिकों के सहयोग से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए हरित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनभागीदारी बनी अभियान की सबसे बड़ी शक्ति

पौधरोपण महाअभियान की सबसे बड़ी विशेषता रही समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों, किसानों, औद्योगिक संस्थानों तथा आम नागरिकों ने मिलकर इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया।

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे केवल पौधे लगाकर ही न रुकें, बल्कि उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षण दें। यही पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक संकल्प है।

संपादकीय दृष्टि

उत्तर प्रदेश का यह महाअभियान केवल पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं, बल्कि विकास और पर्यावरण के संतुलन का जीवंत उदाहरण है। जब सरकार, प्रशासन, औद्योगिक संस्थान और समाज एक साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हरित भविष्य की मजबूत नींव रखी जाती है।

आज आवश्यकता केवल एक पौधा लगाने की नहीं, बल्कि उसे जीवन देने की है। यदि प्रत्येक नागरिक "एक पेड़ मां के नाम" के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल और संतुलित पर्यावरण की अमूल्य धरोहर प्राप्त होगी। ■

"एक पेड़ लगाइए, एक पीढ़ी बचाइए। हरित उत्तर प्रदेश—समृद्ध भारत की मजबूत पहचान।"





संघर्ष से शिखर तक: शिवबती की सफलता ने गढ़ी आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की नई मिसाल

"जब अवसर, संरक्षण और संकल्प साथ हों, तो परिस्थितियाँ नहीं, प्रतिभा भविष्य तय करती है।"

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बालिकागृह निवासी **शिवबती** की प्रेरणादायी सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे टिक नहीं सकतीं। श्रवण दिव्यांग होने, कम उम्र में माता-पिता को खो देने और जीवन के अनेक संघर्षों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर निरंतर आगे बढ़ती रहीं।

जिला प्रशासन कोंडागांव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों ने शिवबती की प्रतिभा को नई दिशा दी। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहतराई (बिलासपुर) में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ने उनकी खेल क्षमता को और निखारा।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल कोष निधि से आधुनिक इंडियन एवं रिकर्व तीरंदाजी उपकरण उपलब्ध कराए जाने से शिवबती को अपनी प्रतिभा को उत्कृष्ट प्रदर्शन में बदलने का अवसर मिला। परिणामस्वरूप उन्होंने **जगदलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय शालेय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।** यह उपलब्धि केवल एक पदक नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम की स्वर्णिम पहचान है।

निर्माणशाला टाइम्स शिवबती की इस प्रेरक यात्रा को समर्पित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि आने वाले समय में वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छत्तीसगढ़ और भारत का गौरव बढ़ाएँगी।

शिवबती की कहानी उन हजारों बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखती हैं। यह सफलता बताती है कि यदि बच्चों को सुरक्षित संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और संवेदनशील मार्गदर्शन मिले, तो वे राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं।

आज शिवबती केवल कोंडागांव बालिकागृह की नहीं, बल्कि "**नारी शक्ति, दिव्यांग सशक्तिकरण** और **समावेशी विकास**" की सशक्त प्रतीक बन चुकी हैं। उनकी उपलब्धि समाज को यह संदेश देती है कि प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती; आवश्यकता केवल अवसर, विश्वास और सही मार्गदर्शन की होती है। ■

सम्मान से स्वावलंबन तक
मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना से बदल रही झारखंड की नारी शक्ति की तस्वीर

मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना: आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई क्रांति

झारखंड सरकार की **मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना** केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वावलंबन का नया अध्याय लिख रही है। यह योजना उन महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखती थीं। कोडरमा जिले में इस योजना के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। योजना से प्राप्त नियमित आर्थिक सहायता को महिलाओं ने केवल घरेलू आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे स्वरोजगार, लघु उद्यम और व्यवसाय विस्तार में निवेश कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। आज यही महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक मजबूती के साथ-साथ समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रेरक पहचान बन चुकी हैं।

छोटी सहायता से बड़े बदलाव की कहानी

चंदवारा की **रीना देवी** ने योजना से मिली राशि को बचाकर कपड़ों की दुकान शुरू की। आज उनका व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ रहा है और वे अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ निभा रही हैं।

इसी प्रकार **गायत्री देवी** ने किराना दुकान स्थापित कर नियमित आय का स्थायी स्रोत बनाया। उनके लिए यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर साबित हुई।



जयनगर की **पूजा देवी** ने राशन दुकान शुरू कर सम्मानजनक आजीविका प्राप्त की, जबकि **सीमा देवी** ने अपनी छोटी दुकान में अतिरिक्त पूंजी लगाकर व्यापार का विस्तार किया और आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

मरकच्चो की **नंदनी कुमारी** ने साबुन निर्माण जैसे स्थानीय उद्यम को नई गति दी। उनके प्रयासों ने न केवल परिवार की आय बढ़ाई बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित किए। वहीं **टुनी कुमारी** ने राशन दुकान शुरू कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और भविष्य में व्यवसाय विस्तार का संकल्प लिया।

महिला सशक्तिकरण का सशक्त मॉडल

मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना यह सिद्ध कर रही है कि जब महिलाओं को समय पर आर्थिक सहयोग और विश्वास मिलता है, तो वे केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास की धुरी बन जाती हैं। यह योजना महिलाओं में बचत, निवेश, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत कर रही है।

आज कोडरमा की अनेक महिलाएं सरकारी सहायता को अवसर में बदलकर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। उनकी उपलब्धियां अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। ■

"मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना" महिलाओं के हाथों में केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, स्वावलंबन और नए सपनों की उड़ान सौंप रही है। कोडरमा की प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि जब सरकार की संवेदनशील योजनाएं जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं, तब विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई देता है। यह योजना 'सशक्त नारी–समृद्ध परिवार–विकसित झारखंड' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल बन चुकी है।"

SHE-LEAPS

डिजिटल सशक्तिकरण से 'लखपति दीदी' तक—ग्रामीण भारत की नई उड़ान

तकनीक, उद्यमिता और महिला शक्ति के संगम से आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव

"जब ग्रामीण महिलाओं के हाथों में तकनीक, वित्तीय सशक्तिकरण और उद्यमिता का सामर्थ्य एक साथ आता है, तब केवल परिवार नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ता है।"

भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज लाखों महिलाएँ अपने परिश्रम, कौशल और नवाचार के बल पर स्वरोज़गार का सशक्त उदाहरण बन रही हैं। इसी परिवर्तन को नई गति देने के उद्देश्य से विकसित **SHE-LEAPS (Self-Help Entrepreneur-Livelihoods and Enterprise Application for Prosperity and Sustainability)** ग्रामीण भारत के डिजिटल भविष्य का आधार बनकर उभरा है।

यह आधुनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं, बल्कि महिला उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल नवाचार और सामाजिक परिवर्तन का समेकित अभियान है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आधुनिक डिजिटल सुविधाओं, बाज़ार, प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करना है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से खुलेगी नए अवसरों की दुनिया



SHE-LEAPS महिलाओं को अपने उद्यम का डिजिटल रिकॉर्ड रखने, उत्पादन की योजना बनाने, विपणन रणनीति तैयार करने, डिजिटल भुगतान अपनाने, बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बनाने और सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा।

इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्थानीय सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। डिजिटल तकनीक का यह समावेश उत्पादों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी सुदृढ़ करेगा।

'लखपति दीदी' मिशन को मिलेगा नई तकनीक का मजबूत आधार

देशभर में चल रहे **'लखपति दीदी'** मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। SHE-LEAPS इस अभियान को डिजिटल गति प्रदान करेगा। व्यवसाय विस्तार, वित्तीय



प्रबंधन, बाज़ार विश्लेषण, प्रशिक्षण और उद्यम विकास की सुविधाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से महिलाओं के लिए आय के नए अवसर सृजित होंगे।

यह पहल लाखों महिलाओं को केवल स्वरोज़गार तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें सफल उद्यमी, रोजगार सृजक और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगा व्यापक परिवर्तन

SHE-LEAPS के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, हथकरघा, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, वन उत्पाद, पारंपरिक शिल्प तथा स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। डिजिटल विपणन और ई-कॉमर्स के माध्यम से इन उत्पादों की पहुँच देश-विदेश के उपभोक्ताओं तक आसान होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

वित्तीय समावेशन से सामाजिक सशक्तिकरण तक

आर्थिक रूप से सशक्त महिला केवल अपने परिवार की आय नहीं बढ़ाती, बल्कि बच्चों की शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास की मजबूत आधारशिला भी रखती है। SHE-LEAPS महिलाओं को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, ऋण, बीमा और वित्तीय योजना जैसी सुविधाओं से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

SHE-LEAPS ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, डिजिटल सशक्तिकरण और उद्यमिता का नया अध्याय है। यह पहल सिद्ध करती है कि जब तकनीक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती है, तब विकास केवल आँकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई देता है। 'लखपति दीदी' मिशन को नई गति देने वाला यह डिजिटल मंच आने वाले वर्षों में लाखों महिलाओं के सपनों को नई उड़ान देगा और विकसित, समावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई शक्ति

डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, स्टार्टअप संस्कृति और ग्रामीण विकास जैसी राष्ट्रीय पहलों को एक मंच पर जोड़ते हुए SHE-LEAPS विकसित भारत की परिकल्पना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह पहल नवाचार, तकनीक और सामाजिक समावेशन के माध्यम से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।

मुख्य विशेषताएँ (Highlights)

- स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
- उद्यम प्रबंधन, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच।
- राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाज़ारों से जुड़ने का अवसर।
- 'लखपति दीदी' मिशन को तकनीकी मजबूती और नई गति।
- महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण आर्थिक विकास को मिलेगा नया आयाम।
- डिजिटल समावेशन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। ■

भारत टेक्स 2026 : टेक्सटाइल महाशक्ति बनने की ओर बिहार का आत्मविश्वासपूर्ण कदम

1,476 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 40,500 से अधिक संभावित रोजगार और वैश्विक मंच पर बिहार की सशक्त पहचान



भारत टेक्स 2026 में पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार की प्रभावशाली भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य अब केवल अपनी समृद्ध हस्तकरघा और पारंपरिक वस्त्र विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक टेक्सटाइल एवं परिधान उद्योग के उभरते निवेश केंद्र के रूप में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन में बिहार सरकार ने निवेश, रोजगार, नवाचार और पारंपरिक कला के अद्भुत समन्वय का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान **16 अग्रणी कंपनियों के साथ 1,476 करोड़** के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापनों **(MoUs)** पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे **40,500 से अधिक संभावित रोजगार** सृजित होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि बिहार की औद्योगिक प्रगति और निवेशकों के बढ़ते विश्वास का सशक्त प्रमाण है।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री **श्री गिरिराज सिंह** एवं बिहार की उद्योग मंत्री **सुश्री श्रेयसी सिंह** ने संयुक्त रूप से बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उद्योग विभाग के **सचिव श्री कुंदन कुमार,** बिहार भवन के स्थानिक आयुक्त **श्री मनोज कुमार सिंह,** हथकरघा एवं रेशम निदेशालय के **डॉ. विद्यानंद सिंह** तथा उद्योग निदेशक **श्री मुकुल कुमार गुप्ता** सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने राज्य की औद्योगिक प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त बनाया।

बिहार पवेलियन में राज्य की पारंपरिक कला और आधुनिक उद्योग का सुंदर संगम देखने को मिला। **मधुबनी चित्रकला, टिकुली कला, तसर सिल्क, खादी, रेशम उत्पाद** तथा आधुनिक परिधान उद्योग से जुड़े उत्पादों ने देश-विदेश से आए निवेशकों और खरीदारों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इससे बिहार की सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ उसके औद्योगिक सामर्थ्य को भी वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली।

राज्य सरकार की **निवेश-अनुकूल नीतियाँ, प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक सुविधाएँ, बेहतर आधारभूत संरचना** तथा **उद्योगोन्मुखी दृष्टिकोण** बिहार को टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना रहे हैं। **"बिहार है तैयार"** की सोच आज निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के रूप में धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है।

"परंपरा की विरासत, आधुनिक उद्योग की रफ्तार और निवेशकों का बढ़ता विश्वास—यही है नए बिहार की पहचान। भारत टेक्स 2026 में बिहार की उपलब्धियाँ आत्मनिर्भर, रोजगारसमृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।"

प्रमुख उपलब्धियाँ

- 1,476 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर 16 कंपनियों के साथ MoU।
- 40,500 से अधिक संभावित रोजगार सृजन।
- भारत टेक्स 2026 में पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार की प्रभावशाली भागीदारी।
- मधुबनी, टिकुली, तसर सिल्क एवं खादी जैसी पारंपरिक कलाओं का वैश्विक प्रदर्शन।
- आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग और पारंपरिक शिल्प का सफल समन्वय।
- निवेशकों के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण एवं प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं का प्रदर्शन। ■

प्रकृति से प्रगति की ओर

उत्तराखंड के नेचर गाइड बने आत्मनिर्भरता और रिवर्स पलायन की नई पहचान





उत्तराखंड ने पर्यटन को केवल प्राकृतिक सौंदर्य के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे **रोजगार, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण** और **ग्रामीण विकास** का प्रभावी माध्यम बना दिया है। मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी द्वारा 180 प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष नेचर गाइडों** को रोजगार पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना इसी दूरदर्शी सोच का सशक्त उदाहरण है।

नेचर गाइड केवल पर्यटकों का मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि वे **उत्तराखंड के जंगलों, वन्यजीवों, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के ब्रांड एम्बेसडर** बनकर प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देते हैं। उनकी भूमिका पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रामनगर का फांटो जोन आज **ईको-टूरिज्म और समुदाय आधारित पर्यटन** का उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभरा है। यहां विकसित ट्री हाउस, वन्यजीव पर्यटन और टाइगर साइटिंग जैसी गतिविधियों ने स्थानीय युवाओं, महिलाओं, होमस्टे संचालकों, वाहन चालकों तथा छोटे व्यापारियों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं।

राज्य सरकार की नीतियों का सकारात्मक परिणाम यह है कि प्रदेश में **रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज की गई है। बड़ी संख्या में युवा अपने गांव लौटकर सम्मानजनक आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है।

प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** के मार्गदर्शन में राज्य सरकार **होमस्टे, ईको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, शीतकालीन पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग** और **आध्यात्मिक पर्यटन** जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर पर्यटन को विकास का मजबूत आधार बना रही है। इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार, ग्रामीण परिवारों को आय और युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

आज उत्तराखंड के गांव केवल स्मृतियों का केंद्र नहीं, बल्कि **नई संभावनाओं, हरित रोजगार, प्रकृति संरक्षण** और **समृद्ध भविष्य** के प्रतीक बन रहे हैं। नेचर गाइडों की यह पहल आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

मुख्य सकारात्मक बिंदु

- **180 प्रशिक्षित नेचर गाइडों** को रोजगार पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- **ईको-टूरिज्म** के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार।
- **फांटो जोन** समुदाय आधारित पर्यटन का सफल मॉडल।
- **44% रिवर्स पलायन** से गांवों में बढ़ा रोजगार और विश्वास।
- नेचर गाइड बने **वन्यजीव संरक्षण एवं उत्तराखंड की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर**।
- पर्यटन से मजबूत हो रही स्थानीय अर्थव्यवस्था और साकार हो रहा **आत्मनिर्भर उत्तराखंड**। ■

वैश्विक मंच पर झारखंड की दमदार दस्तक

भारत टेक्स 2026 में तसर सिल्क, जनजातीय कला और एमएसएमई की चमक ने बढ़ाया राज्य का गौरव







नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित **भारत टेक्स 2026** में झारखंड ने अपनी समृद्ध वस्त्र, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन कर वैश्विक खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया। समापन दिवस पर **उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल** ने झारखंड पवेलियन का भ्रमण कर राज्य के **जीआई टैग प्राप्त उत्पादों, तसर सिल्क, हस्तकरघा, जनजातीय हस्तशिल्प** एवं **बांस आधारित उत्पादों** का अवलोकन किया तथा उनकी गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक संभावनाओं की सराहना की।

उद्योग सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain)** से जोड़ना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और एमएसएमई इकाइयों को स्थायी बाजार, बेहतर आय और निर्यात के नए अवसर प्राप्त हो सकें। भारत टेक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन इस दिशा में प्रभावी सेतु का कार्य कर रहे हैं।

झारखंड का **तसर सिल्क** पवेलियन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। तसर से निर्मित परिधान, स्टोल, स्कार्फ और गृह-सज्जा उत्पादों को देश-विदेश के खरीदारों ने विशेष सराहना दी। देश के प्रमुख तसर उत्पादक राज्यों में शामिल झारखंड के हजारों ग्रामीण एवं आदिवासी परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। राज्य सरकार जीआई टैग उत्पादों, जनजातीय कला, हस्तकरघा और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों को आधुनिक विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

120 से अधिक देशों के खरीदारों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति वाले भारत टेक्स 2026 ने झारखंड के उद्यमियों के लिए वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क तक पहुँच का सशक्त अवसर उपलब्ध कराया। इस मंच पर स्थापित नए व्यावसायिक संपर्क राज्य के निर्यात विस्तार, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों, बुनकरों और हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने का नया मार्ग मिला है।

भारत टेक्स 2026 में झारखंड की प्रभावशाली सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक उद्योग, नवाचार और वैश्विक व्यापार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्थानीय शिल्प, पारंपरिक कौशल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने की यह पहल न केवल झारखंड की पहचान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा रही है, बल्कि राज्य के लाखों कारीगरों और उद्यमियों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। ■

कृषि नेतृत्व का राष्ट्रीय सम्मान: प्राकृतिक खेती और नवाचार से समृद्ध भारत की ओर



नई दिल्ली में आयोजित **17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड समारोह** ने भारतीय कृषि के विकास, नवाचार और सतत कृषि प्रणाली के प्रति देश की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा प्रदान की। समारोह में राज्यपाल **श्री हरिभाऊ बागडे** तथा रक्षा मंत्री **श्री राजनाथ सिंह** ने विभिन्न राज्यों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। प्रमुख श्रेणियों में **उत्तर प्रदेश** और **गुजरात** को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया, जिसे संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों ने ग्रहण किया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री बागडे ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की कृषि प्रगति का अगला चरण **प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण** और **जल प्रबंधन** पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि केवल अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और ग्रामीण समृद्धि की आधारशिला है। आज भी देश की बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने हरित क्रांति के जनक **डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन** के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया, उसी प्रकार अब समय **पोषण-सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य** और **पर्यावरण संरक्षण** को प्राथमिकता देने का है। इसके लिए प्राकृतिक खेती, वर्षा जल संचयन, कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाना आवश्यक है।

यह समारोह केवल पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि **सतत कृषि, नवाचार और किसान-केंद्रित विकास** के राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा। राज्यों के उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और अन्य प्रदेशों को भी कृषि सुधारों एवं नवाचारों की दिशा में प्रेरणा मिलेगी। ■

निर्माणशाला टाइम्स की दृष्टि से यह आयोजन इस बात का सशक्त संदेश देता है कि 'सम्मान, नवाचार और सतत विकास' ही भारतीय कृषि का भविष्य हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, आधुनिक तकनीकों के समावेश और किसानों की सहभागिता से भारत आत्मनिर्भर, समृद्ध और पर्यावरण-अनुकूल कृषि व्यवस्था की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

मिनी नंदिनी योजना से बदली तकदीर

गोसेवा से डेयरी उद्यमिता तक: प्रतापगढ़ के युवा शिवम सिंह ने रचा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय



ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती केवल खेती तक सीमित नहीं है। पशुपालन और डेयरी आधारित उद्यम आज किसानों और युवाओं के लिए स्थायी आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना इस दिशा में एक प्रभावी पहल है, जिसने अनेक परिवारों को आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। प्रतापगढ़ के शिवम सिंह की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही योजना, दृढ़ संकल्प और आधुनिक तकनीक के समन्वय से गांवों में भी समृद्धि का नया अध्याय लिखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की **मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना** ग्रामीण युवाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक डेयरी उद्यमिता, स्वदेशी गोवंश संरक्षण और ग्रामीण रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को भी साकार कर रही है। प्रतापगढ़ जनपद के सांड़वा चंडिका गांव निवासी शिवम सिंह की सफलता इसकी प्रेरक मिसाल है।

घायल गाय की सेवा से शुरू हुई सफलता की कहानी

करीब पाँच वर्ष पूर्व शिवम सिंह के पिता राकेश सिंह को रास्ते में एक घायल देशी गाय मिली। परिवार ने उसे घर लाकर सेवा-भाव से उसका उपचार किया। इसी घटना ने परिवार में गोपालन के प्रति गहरा लगाव पैदा किया। समय के साथ गायों की संख्या बढ़ती गई और यह छोटा प्रयास एक संगठित डेयरी उद्यम का रूप लेने लगा।

योगी सरकार की योजना बनी टर्निंग प्वाइंट

इसी दौरान शिवम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की **मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना** की जानकारी मिली। आवेदन के बाद योजना के अंतर्गत उन्हें पाँच लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस सहायता से उन्होंने राजस्थान से उच्च गुणवत्ता वाली **गिर** और **साहीवाल** नस्ल की दस गायें खरीदीं तथा आधुनिक डेयरी की स्थापना की। आज उनकी डेयरी में लगभग **25 गोवंश** हैं और प्रतिदिन करीब **110 लीटर दूध** का उत्पादन हो रहा है। डेयरी व्यवसाय से उन्हें **20 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय** प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

ए2 दूध और स्वदेशी नस्ल संरक्षण की दिशा में पहल

शिवम सिंह आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए स्वदेशी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य **ए2 दूध,** शुद्ध घी तथा अन्य मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और विपणन के माध्यम से अपनी अलग पहचान स्थापित करना है। साथ ही वे उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लों के ब्रीड डेवलपमेंट पर भी कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरक उदाहरण

शिवम सिंह की यात्रा यह सिद्ध करती है कि सेवा-भाव, आधुनिक सोच और सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है। एक घायल गाय की सेवा से शुरू हुआ यह सफर आज सफल डेयरी उद्यम, स्वदेशी गोवंश संरक्षण और ग्रामीण रोजगार का प्रेरणादायक मॉडल बन चुका है।

मुख्य उपलब्धियां एक नजर में

- योजना: **मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना**
- लाभार्थी: **शिवम सिंह, प्रतापगढ़**
- योजना के तहत प्राप्त ऋण: **5 लाख**
- कुल गोवंश: **25**
- प्रतिदिन दूध उत्पादन: **लगभग 110 लीटर**
- वार्षिक आय: **20 लाख से अधिक**
- भविष्य की योजना: **ए2 दूध, घी एवं मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों का उत्पादन तथा स्वदेशी नस्ल संरक्षण** ■

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहल

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट-2026' से उद्योगों को नई उड़ान

जोखिम आधारित व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़, MSME सेक्टर को मिलेगा अभूतपूर्व लाभ

व्यापार और उद्योगों के लिए पारदर्शी, सरल तथा विश्वास-आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विधानसभा द्वारा पारित **'छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अधिनियम, 2026'** राज्य को देश का पहला ऐसा प्रदेश बनाता है, जहाँ उद्योगों और व्यवसायों के लिए **जोखिम (Risk) आधारित नियामक प्रणाली** लागू की जाएगी। यह अधिनियम केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था में **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस से ईज़ ऑफ़ लिविंग'** की सोच को भी सशक्त करता है। इससे छोटे, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यमों (MSME) को अनावश्यक प्रशासनिक बोझ से राहत मिलेगी और वे अधिक ऊर्जा उत्पादन, नवाचार तथा रोजगार सृजन में लगा सकेंगे।

MSME क्षेत्र के लिए विकास का स्वर्णिम अवसर

नई व्यवस्था के अंतर्गत छोटे एवं कम जोखिम वाले उद्योगों को **सेल्फ-सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन** तथा **समयबद्ध स्वीकृति** जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। इससे लाइसेंस, भवन स्वीकृति, औद्योगिक पंजीकरण और अन्य सरकारी सेवाएँ पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ और सरल होंगी। हर वर्ष लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त होने से उद्यमियों का समय और लागत दोनों बचेंगे।

पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही का नया मॉडल

इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम जोखिम वाले उद्योगों में बार-बार निरीक्षण की आवश्यकता कम होगी, जबकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी जारी रहेगी। इससे शासन में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का संतुलित मॉडल विकसित होगा।

निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार का अनुमान है कि राज्य के लगभग **15 लाख MSME** उद्यमी इस सुधार का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करेंगे। सरल प्रक्रियाएँ, त्वरित अनुमोदन और कम अनुपालन लागत राज्य में नए निवेश को आकर्षित करेंगी, जिससे स्थानीय उद्योगों का विस्तार होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।



'छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अधिनियम, 2026' केवल एक नया कानून नहीं, बल्कि विश्वास-आधारित सुशासन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त सुधार है। यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उद्यमिता को नई गति देगी, निवेश का वातावरण मजबूत करेगी तथा भारत के औद्योगिक विकास मॉडल को नई दिशा प्रदान करेगी।

सुशासन की दिशा में दूरदर्शी पहल

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति तथा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति इस व्यवस्था की निगरानी करेंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सेवा समयबद्ध, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल ढंग से उपलब्ध हो। ■



उत्तर प्रदेश की टेक उड़ान

एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक का नया राष्ट्रीय केंद्र

उत्तर प्रदेश ने भविष्य की अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी आधारित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य को **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और डीप टेक** का अग्रणी केंद्र बनाने की व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह पहल उत्तर प्रदेश को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि **वैश्विक नवाचार, अनुसंधान** और **उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण का नेतृत्वकर्ता** बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

'प्रगति' परियोजना: भारत के सबसे बड़े रोबोटिक्स क्लस्टर की शुरुआत

नोएडा में लगभग **75 एकड़ क्षेत्र** में विकसित होने वाली **PRAGATI (Park for Robotics, Artificial Intelligence, GPU Clusters and Advanced Technical Innovation)** परियोजना देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगी। यहां अत्याधुनिक **रोबोटिक्स टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन सेंटर, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू क्लस्टर्स, डेटा सेंटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन हब, रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब तथा अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं** विकसित की जाएंगी। यह परियोजना भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है।

'यू हब': नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र

लखनऊ और नोएडा में स्थापित होने वाले **यू हब** अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को एक साझा मंच प्रदान करेंगे। वित्तीय वर्ष **2026-27** में इसके लिए **100 करोड़** रुपये का प्रावधान किया गया है। यहां विकसित होने वाला डीप टेक इकोसिस्टम **क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिकल एआई, सेमीकंडक्टर डिजाइन, रक्षा प्रौद्योगिकी, हेल्थ एआई, एग्री बायोटेक और गवटेक** जैसे क्षेत्रों में नवाचार को नई गति देगा।

भविष्य के कौशल, युवाओं के सुनहरे अवसर

राज्य सरकार युवाओं को **एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर तकनीक** जैसे उभरते क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने पर विशेष बल दे रही है। उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करेंगे तथा अनुसंधान से उद्यमिता तक का सशक्त मार्ग प्रशस्त करेंगे।

निवेश, नवाचार और रोजगार का नया युग

नोएडा की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, **जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा** और

उत्तर प्रदेश की यह दूरदर्शी पहल 'नवाचार से आत्मनिर्भरता और तकनीक से समृद्धि' के संकल्प को साकार करती है। रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप टेक पर आधारित यह नई विकास यात्रा न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी, बल्कि भारत को वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। यह पहल युवाओं के सपनों, उद्योगों की प्रगति और राष्ट्र के तकनीकी भविष्य को एक नई ऊर्जा देने वाला परिवर्तनकारी अभियान है।

विकसित औद्योगिक आधार इस परियोजना को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। अनुमान है कि इस पहल से **एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार** सृजित होंगे तथा अगले पांच वर्षों में **दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का सकल मूल्य संवर्धन** होगा।

टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचेगी डिजिटल क्रांति

नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के माध्यम से आईटी उद्योग का विस्तार केवल नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित न रहकर **टियर-2** और **टियर-3** शहरों तक किया जाएगा। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, स्टार्टअप संस्कृति और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों का समान विकास सुनिश्चित होगा। ■

डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई उड़ान

हरियाणा-फ्लिपकार्ट साझेदारी से किसानों, एमएसएमई और युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर

नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कल्याण कृष्णमूर्ति के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि हरियाणा अब कृषि, उद्योग और डिजिटल व्यापार को एकीकृत करते हुए नई विकास यात्रा की ओर बढ़ रहा है। बैठक में रजनीश कुमार भी उपस्थित रहे।



बैठक में किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और स्थानीय उत्पादकों को डिजिटल मार्केटप्लेस से जोड़ने की रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई। यदि यह पहल प्रभावी रूप से लागू होती है तो हरियाणा के उत्पाद देशभर के उपभोक्ताओं तक अधिक तेज़ी और बेहतर मूल्य के साथ पहुँच सकेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलने की संभावना है।

विशेष रूप से हॉर्टिकल्चर और फ्रेश प्रोड्यूस सोर्सिंग को तकनीक आधारित सप्लाई चेन से जोड़ने पर जोर दिया गया। इससे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बिचौलियों पर निर्भरता कम करते हुए सीधे बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। आधुनिक लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं विपणन क्षमता में भी सुधार होगा।

बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों पर विचार-विमर्श रहा। डिजिटल कॉमर्स, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स सेवाओं के विस्तार से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय उद्यमियों और एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा।

फ्लिपकार्ट समूह ने हरियाणा के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्य में किसानों, उद्यमियों और स्थानीय व्यवसायों के लिए नए अवसर सृजित करने का विश्वास व्यक्त किया। यह पहल केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, नवाचार और समावेशी विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं सशक्त हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ■

सुगंध से सफलता तक
यूपी की 'विदुर हर्बल टी' बनी महिला आत्मनिर्भरता की नई पहचान

गांव की रसोई से वैश्विक बाजार तकः 'विदुर हर्बल टी' की प्रेरक उड़ान





उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की नई कहानी अब जड़ी-बूटियों की सुगंध के साथ दुनिया तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने **'विदुर हर्बल टी'** के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग मिले तो गांव की महिलाएं भी वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकती हैं।

एक लाख के ऋण से शुरू हुआ लाखों का सपना

बिजनौर के टांडा मैदास लखी वाला गांव की महिलाओं ने मात्र **एक लाख रुपये के ऋण** से हर्बल टी निर्माण का कार्य शुरू किया। आज यही प्रयास सफल महिला उद्यमिता का उदाहरण बन चुका है। समूह की महिलाएं न केवल नियमित आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों की आर्थिक मजबूती का आधार भी बनी हैं।

प्राकृतिक स्वास्थ्य का भरोसा

'विदुर हर्बल टी' पूरी तरह प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से तैयार की जाती है। लेमनग्रास, गिलोय, तुलसी, मुलेठी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, हरी इलायची, सौंफ, जामुन और अमरूद की पत्तियों जैसे औषधीय तत्व इसे विशेष बनाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के दौर में यह उत्पाद लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

देश से विदेश तक बढ़ती पहचान

आज 'विदुर हर्बल टी' की मांग दिल्ली, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में लगातार बढ़ रही है। वहीं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में इसकी फ्रेंचाइजी स्थापित करने की तैयारियां इस बात का प्रमाण हैं कि स्थानीय उत्पाद भी वैश्विक पहचान बना सकते हैं।

महिलाएं संभाल रही हैं पूरी जिम्मेदारी

इस उद्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्पादन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन तक की पूरी प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संचालित करती हैं। इससे महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन का नया अध्याय जुड़ा है।

'विदुर हर्बल टी' केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त कहानी है। यह पहल बताती है कि जब सरकारी योजनाएं, स्थानीय संसाधन और महिलाओं का संकल्प एक साथ जुड़ते हैं, तो गांव की छोटी-सी शुरुआत भी विश्व बाजार तक अपनी सुगंध पहुंचा सकती है। उत्तर प्रदेश की यह सफलता देशभर की ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का उज्ज्वल उदाहरण है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा

बिजनौर और मुरादाबाद में अनेक आउटलेट एवं हर्बल टी सेंटर संचालित हो रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। ■

इंजीनियर से एग्री-उद्यमी तक: युवा शक्ति ने लिखी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नई कहानी

"जब युवा अवसरों को पहचानते हैं, तो गांव विकास का केंद्र बन जाते हैं।"

उत्तर प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को नई ऊर्जा देने की दिशा में सरकार की योजनाएं अब केवल कागज़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन की प्रेरक कहानियां बन रही हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और योगी सरकार की उद्यमिता-समर्थक नीतियों ने अनेक युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी के रूप में स्थापित किया है।

रायबरेली के मत्स्य उद्यमी **सुजीत चौधरी** इसका सशक्त उदाहरण हैं। अमेरिका में सफल इंजीनियरिंग करियर छोड़कर उन्होंने अपने





अनुभव और आधुनिक तकनीक को गांव की मिट्टी से जोड़ा। वर्ष 2019 में रायबरेली के महराजगंज क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक मत्स्य उत्पादन केंद्र स्थापित कर उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं का द्वार खोला।

आज 23 वैज्ञानिक तालाबों में प्रतिवर्ष **500–600 टन मछली** का उत्पादन हो रहा है। इससे न केवल उनकी अपनी आय बढ़ी है, बल्कि **50 से अधिक किसान** भी इस मॉडल



"सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं, जब युवा उन्हें अवसर में बदल दें। रायबरेली का यह मत्स्य मॉडल बताता है कि नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के बल पर गांव भी विकास और समृद्धि के नए केंद्र बन सकते हैं। यही है नए भारत के आत्मविश्वासी युवा की पहचान।"

से जुड़कर बेहतर आमदनी अर्जित कर रहे हैं। बिचौलियों पर निर्भरता कम करते हुए सीधे बाजार से जुड़ने की उनकी रणनीति किसानों के लिए भी प्रेरणादायक बन गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्राप्त **8.50 लाख रुपये के अनुदान** ने इस उद्यम को नई गति दी। अब प्रस्तावित **फिश हब, आधुनिक प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र** स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। यह पहल मत्स्य पालन को केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बना रही है।

सुजीत चौधरी की सफलता यह सिद्ध करती है कि यदि सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग, आधुनिक तकनीक और दृढ़ संकल्प का समन्वय हो, तो गांवों में भी विश्वस्तरीय उद्यम खड़े किए जा सकते हैं। ऐसे प्रयास "**आत्मनिर्भर भारत**" और "**विकसित उत्तर प्रदेश**" के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ■



देवभूमि बनेगी ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशनः उत्तराखंड में पर्यटन, निवेश और रोजगार का नया स्वर्णिम अध्याय

उत्तराखंड सरकार "वेड इन उत्तराखंड" अभियान के माध्यम से राज्य को विश्वस्तरीय डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री **श्री पुष्कर सिंह धामी** के नेतृत्व में यह पहल केवल पर्यटन को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने का भी सशक्त माध्यम बन रही है।

देवभूमि की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से **त्रियुगीनारायण, ऊखीमठ, टिहरी, मसूरी और रामनगर** जैसे स्थलों को विश्वस्तरीय डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह स्थल त्रियुगीनारायण मंदिर को इस अभियान का प्रमुख आकर्षण बनाया जा रहा है, जिससे भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी।

"वेड इन उत्तराखंड" केवल एक पर्यटन अभियान नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था, प्रकृति और आर्थिक समृद्धि का अभिनव संगम है। यह पहल स्थानीय रोजगार, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सतत पर्यटन को नई दिशा देते हुए उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने की क्षमता रखती है। देवभूमि का यह परिवर्तन भारत के पर्यटन विकास मॉडल का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभर रहा है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई उड़ान

डेस्टिनेशन वेडिंग केवल विवाह आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बन रही है। इससे स्थानीय कारीगरों, लोक कलाकारों, होमस्टे संचालकों, टैक्सी चालकों, फोटोग्राफरों, फ्लोरिस्ट, कैटरिंग सेवाओं तथा छोटे व्यापारियों के लिए आय के नए अवसर सृजित होंगे। यह पहल आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यटन के नए आयाम: वेलनेस और आध्यात्म का संगम

राज्य सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ-साथ **स्पिरिचुअल एवं वेलनेस टूरिज्म** को भी समान प्राथमिकता दे रही है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान पर आधारित विश्वस्तरीय सुविधाओं के विकास से उत्तराखंड वैश्विक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, केदारखंड, मानसखंड तथा प्रस्तावित स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन इस दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश का सशक्त आधार

चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, आधुनिक रोपवे, हवाई अड्डों का विस्तार और प्रदेशभर में विकसित किए जा रहे हेलीपोर्ट पर्यटन को नई गति प्रदान करेंगे। साथ ही **सिंगल विंडो क्लीयरेंस,** निवेश-अनुकूल नीतियां और बेहतर कानून-व्यवस्था उत्तराखंड को देश के सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्यों में स्थापित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री का विजन

मुख्यमंत्री **श्री पुष्कर सिंह धामी** ने राष्ट्रीय वेडिंग प्रोफेशनल्स सम्मेलन में देशभर के वेडिंग प्लानर्स, इवेंट विशेषज्ञों और निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री **श्री नरेंद्र मोदी** की **"वेड इन उत्तराखंड"** परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी हितधारकों के सहयोग से उत्तराखंड शीघ्र ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। ■

दिल्ली से हरियाणा की ओर व्यापार का नया अध्याय

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वस्तरीय ट्रेड हब का रखा विजन

थोक व्यापारियों से सीधा संवाद, आधुनिक मार्केट, नमो सिटी और निवेश-अनुकूल नीतियों के साथ हरियाणा बनने जा रहा है देश का अगला बड़ा व्यापारिक केंद्र

देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की भूमिका केवल वस्तुओं के क्रय-विक्रय तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उत्पादन, रोजगार और विकास की मजबूत कड़ी हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में दिल्ली की 26 प्रमुख व्यापारिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश को देश के सबसे आधुनिक और निवेश-अनुकूल व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने का स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती भीड़भाड़ और सीमित स्थान की चुनौती को देखते हुए हरियाणा में विश्वस्तरीय व्यापारिक मार्केट विकसित की जाएगी, जहां चौड़ी सड़कें, आधुनिक लॉजिस्टिक्स, हरित वातावरण, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह केवल एक बाजार नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाने वाला समग्र व्यापारिक इकोसिस्टम होगा।



बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्बल, ड्राई फ्रूट, लोहा मंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों ने अपने सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार उनके साथ साझेदार की भूमिका निभाएगी और किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार के द्वार सदैव खुले रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर और लुधियाना के अनेक व्यापारियों द्वारा हरियाणा में प्लॉट लेकर नई व्यापारिक संभावनाओं की शुरुआत की जा चुकी है। यह विश्वास दर्शाता है कि हरियाणा तेजी से उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

इस अवसर पर लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित **'नमो सिटी'** का भी उल्लेख किया गया, जिसमें आधुनिक व्यावसायिक, आवासीय और नागरिक सुविधाओं का समावेश होगा। यह परियोजना व्यापार, निवेश, रोजगार और शहरी विकास का नया मॉडल बनने की क्षमता रखती है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, समयबद्ध स्वीकृति, रोजगार आधारित प्रोत्साहन तथा कस्टमाइज्ड इंसेंटिव जैसी नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य निवेशकों के लिए सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण उपलब्ध कराना है। राई स्थित मारुति के विशाल संयंत्र, खरखौदा के औद्योगिक विकास और प्रस्तावित हॉर्टिकल्चर मंडी जैसी परियोजनाएं हरियाणा की औद्योगिक प्रगति को नई गति दे रही हैं।

उद्योग मंत्री श्री राव नरबीर ने भी हरियाणा की उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, बेहतर सड़क संपर्क, एनसीआर से निकटता और विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टरों का उल्लेख करते हुए व्यापारियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ■

हरियाणा सरकार की यह पहल केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के व्यापारिक ढांचे को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की एक दूरदर्शी सोच का परिचायक है। यदि प्रस्तावित विश्वस्तरीय मार्केट, नमो सिटी और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना समयबद्ध रूप से विकसित होती है, तो हरियाणा आने वाले वर्षों में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और लॉजिस्टिक हब बन सकता है। यह पहल न केवल व्यापारियों को नई संभावनाएं प्रदान करेगी, बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और ₹विकसित भारत₹ के संकल्प को भी नई ऊर्जा देगी।



बिहार का 'मेगा इन्वेस्टमेंट मिशन': 31 दिसंबर तक बढ़ा सुनहरा अवसर, उद्योगों के लिए खुला विकास का नया द्वार

निवेश, रोजगार और आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ता सशक्त कदम

औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने की दिशा में बिहार सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज–2025** की अवधि **31 दिसंबर, 2026** अथवा नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 लागू होने तक बढ़ा दी है। यह निर्णय उन उद्यमियों और निवेशकों के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है, जो बिहार की औद्योगिक क्षमता पर विश्वास जताते हुए यहाँ निवेश करना चाहते हैं।

यह पहल केवल समय-सीमा का विस्तार नहीं, बल्कि बिहार को **पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र** बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। राज्य सरकार का लक्ष्य बड़े निवेश आकर्षित करना, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा आने वाले वर्षों में **एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर** सृजित करना है।

निवेशकों के लिए ऐतिहासिक प्रोत्साहन

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज देश की सबसे आकर्षक औद्योगिक योजनाओं में शामिल है। इसके अंतर्गत बड़े निवेशकों को **मात्र एक रुपये की सांकेतिक राशि पर भूमि उपलब्ध कराने** जैसी अभिनव व्यवस्था की गई है। विभिन्न निवेश श्रेणियों के अनुसार 10 से 25 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, अन्य निवेशकों को भी बियाडा की निर्धारित दरों पर **50 प्रतिशत तक की छूट** का लाभ मिलेगा।

यह नीति स्पष्ट संदेश देती है कि बिहार अब केवल संभावनाओं का राज्य नहीं, बल्कि **अवसरों की धरती** बन चुका है।

रोजगार, उद्यमिता और समृद्धि का नया अध्याय

राज्य सरकार का विश्वास है कि उद्योगों के विस्तार से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे बिहार में निवेश, उत्पादन, निर्यात और उद्यमिता का नया दौर शुरू होगा।

'मेक इन बिहार' को मिलेगी नई उड़ान

बढ़ी हुई समय-सीमा निवेशकों को योजनाबद्ध तरीके से परियोजनाएँ तैयार करने का अवसर देगी। यह कदम बिहार की निवेश-अनुकूल नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और औद्योगिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आने वाले समय में यह निर्णय राष्ट्रीय एवं वैश्विक कंपनियों को बिहार की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ■

"जहाँ उद्योग आते हैं, वहीं रोजगार, समृद्धि और विकास की नई राहें खुलती हैं।"

बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की अवधि बढ़ाना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, औद्योगिक और समृद्ध बिहार के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। यह पहल निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी और बिहार को देश के उभरते औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भारत की ऐतिहासिक छलांग

पचपदरा रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स: विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति

'ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सामर्थ्य का आधार है।" इसी सोच को साकार करते हुए राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थापित **पचपदरा रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स** राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। यह परियोजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, औद्योगिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में शामिल यह कॉम्प्लेक्स भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने तथा घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना पश्चिमी भारत को एक नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

राजस्थान बनेगा ऊर्जा और उद्योग का नया केंद्र

पचपदरा परियोजना ने बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएँ खोल दी हैं। इससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा तथा परिवहन, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक मानचित्र को नई पहचान देगी।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा नया आधार

यह परियोजना 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' और 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विज़न को मजबूत आधार प्रदान करती है। अत्याधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन का उत्पादन, पेट्रोकेमिकल उद्योग का विस्तार तथा वैश्विक स्तर की उत्पादन क्षमता



भारत को ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाएगी।

मुख्य विशेषताएँ

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती।
- पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता में कमी। आधुनिक रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता का विस्तार।
- हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर।
- बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति।
- सड़क, रेल, बिजली और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विस्तार।
- स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन।
- 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। ■

पचपदरा रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की ऊर्जा, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह परियोजना बताती है कि दूरदर्शी नीतियाँ, आधुनिक तकनीक और मजबूत संकल्प मिलकर किसी भी क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। आने वाले वर्षों में यह कॉम्प्लेक्स न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक निवेश के प्रमुख केंद्रों में भी स्थापित करेगा।

"ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत—समृद्ध भारत, सक्षम भारत और विकसित भारत की मजबूत नींव।"



देवभूमि के विकास में कॉर्पोरेट सहभागिता का नया अध्याय

'उत्तराखंड CSR डायलॉग' से विकास, रोजगार और सामाजिक परिवर्तन को मिली नई दिशा

उत्तराखंड की समावेशी एवं सतत विकास यात्रा को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** की पहल पर आयोजित **'उत्तराखंड CSR डायलॉग'** केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार, उद्योग जगत और समाज के बीच साझा उत्तरदायित्व का सशक्त मंच बनकर उभरा। इस संवाद में विभिन्न प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूहों, केंद्रीय उपक्रमों एवं सामाजिक संस्थाओं ने राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि **देवभूमि में किया गया प्रत्येक सामाजिक निवेश केवल CSR व्यय नहीं, बल्कि मानवता, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में योगदान है।** उन्होंने उद्योग समूहों से अपील की कि उत्तराखंड में संचालित कंपनियाँ अपने CSR संसाधनों का अधिकतम उपयोग राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में करें।

> **"जब सरकार की दूरदर्शी सोच, उद्योगों की सामाजिक प्रतिबद्धता और समाज की सहभागिता एक साथ आगे बढ़ती है, तभी विकास का वास्तविक मॉडल तैयार होता है। 'उत्तराखंड CSR डायलॉग' इसी साझेदारी का सशक्त उदाहरण है, जो देवभूमि के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा।"**

समग्र विकास का विजन

पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड की विकास संबंधी चुनौतियाँ अन्य राज्यों से भिन्न हैं। ऐसे में सरकार का लक्ष्य केवल आधारभूत ढाँचे का विस्तार नहीं, बल्कि **रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास** और **ग्रामोदय** के माध्यम से संतुलित एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत की आधुनिक कार्यशैली, तकनीकी दक्षता और सामाजिक प्रतिबद्धता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

CSR से बदलेगा उत्तराखंड का भविष्य

कार्यक्रम के दौरान **हुंडई, इंफोसिस फाउंडेशन, ओएनजीसी, आईटीसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, आदित्य बिरला कैपिटल, फिनोलेक्स और पैनासोनिक** सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ शिक्षा, सड़क सुरक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। यह पहल राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उद्योगों के लिए भरोसेमंद निवेश गंतव्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त **3.56 लाख करोड़ रुपये** से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से **1 लाख करोड़ रुपये** से अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, 30 से अधिक उद्योगोन्मुखी नीतियाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा तथा 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड जैसी पहलें उत्तराखंड को देश के सबसे भरोसेमंद निवेश राज्यों में स्थापित कर रही हैं।

पारदर्शिता से बढ़ा उद्योगों का विश्वास

राज्य सरकार की **जीरो टॉलरेंस टू करप्शन** नीति ने उद्योगों का विश्वास मजबूत किया है। पारदर्शी प्रशासन, सरल लाइसेंसिंग प्रक्रिया और निवेश-अनुकूल वातावरण ने उद्यमियों के लिए कार्य करना पहले से अधिक सुगम बनाया है। यही कारण है कि उत्तराखंड को **Ease of Doing Business** में Achiever तथा **Startup Ranking** में Leader का दर्जा प्राप्त हुआ है। ■

सहकार से समृद्धि: ग्रामीण भारत के विकास का नया अध्याय

सहकारिता मंत्रालय के पाँचवें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि सहकारिता अब केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में स्थापित सहकारिता मंत्रालय ने बीते पाँच वर्षों में सहकारी क्षेत्र को नई दिशा, आधुनिक तकनीक और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्रदान की है।



डिजिटल सहकारिता: पारदर्शिता और सुशासन की नई पहचान

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के साथ सहकारी संस्थाओं को तकनीक से जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया गया है। ई-पैक्स प्रणाली, डिजिटल भुगतान व्यवस्था तथा ऑनलाइन अंकेक्षण जैसी पहल ने सहकारी संस्थाओं के कामकाज को अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। आज किसानों को समयबद्ध भुगतान, डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

राजस्थान बना सहकारिता मॉडल का अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन गांव-ढाणी तक पहुँच चुका है। प्रदेश में 42 हजार से अधिक सहकारी समितियों से 1.35 करोड़ सदस्य जुड़े हैं तथा हाल ही में 8.90 लाख नए सदस्य इस परिवार का हिस्सा बने हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति स्थापित करने का लक्ष्य राज्य को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बना रहा है।

डेयरी सहकारिता से बढ़ी ग्रामीण समृद्धि

राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों के लिए आर्थिक आधार बन चुका है। राज्य में दूध संकलन 38 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 45 लाख लीटर तक पहुँच गया है। 9.40 लाख दुग्ध उत्पादकों में 4.20 लाख से अधिक महिलाएँ शामिल हैं, जो महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। घाटे में चल रहे डेयरी संघों का लाभ में आना तथा 10 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टर्नओवर इस परिवर्तन की बड़ी उपलब्धि है।

ई-पैक्स से मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था

राजस्थान में प्रथम चरण में 5,646 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें ई-पैक्स में परिवर्तित किया जा चुका है। इनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन सम्पन्न हुए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। आज ई-पैक्स केवल कृषि ऋण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र तथा किसान उत्पादक संगठनों जैसी अनेक सेवाओं का भी संचालन कर रहे हैं।

सहकारिता में नवाचार की नई उड़ान

समारोह के दौरान देशभर में 50 हजार पैक्स के ई-पैक्स रूपांतरण, अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत नए गोदामों के निर्माण एवं हस्तांतरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियो टैग मोबाइल एप तथा डेयरी सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड जैसे अनेक नवाचारों का शुभारंभ किया गया। इससे सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।

सहकारिता आज केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तीकरण, डिजिटल सुशासन और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का आधार बन चुकी है। आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और जनभागीदारी के माध्यम से सहकारिता आंदोलन देश के विकास की नई इबारत लिख रहा है। राजस्थान का मॉडल इस परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है, जो "सहकार से समृद्धि" के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायी भूमिका निभा रहा है।

राजस्थान को मिली विकास की नई सौगातें

समारोह में राजस्थान को 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण तथा 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण जैसी महत्वपूर्ण सौगातें मिलीं। साथ ही जयपुर के सुमेल गाँव में 64 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले **'सहकार वन'** का ई-भूमि पूजन भी किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल है। ■

एक संवेदना से शुरू हुई स्वास्थ्य क्रांति

हरियाणा की टेली-ईसीजी सेवा: 'गोल्डन ऑवर' में जीवन बचाने का नया भरोसा





स्वास्थ्य सेवाओं में वास्तविक परिवर्तन तब आता है, जब नीतियाँ केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित हों। हरियाणा में शुरू की गई **टेली-ईसीजी सेवा** इसी सोच का जीवंत उदाहरण है। एक ऐसी दुखद घटना, जिसमें समय पर ईसीजी जांच उपलब्ध न होने के कारण एक मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी, ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री **आरती सिंह राव** को गहराई से प्रभावित किया। उसी संवेदना ने एक ऐसी पहल को जन्म दिया, जो आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद और जीवन का नया आधार बन चुकी है।

'गोल्डन ऑवर' में समय पर उपचार, सैकड़ों परिवारों की मुस्कान

दिल का दौरा पड़ने के बाद का पहला घंटा चिकित्सा विज्ञान में 'गोल्डन ऑवर' माना जाता है। इसी समय सही जांच और त्वरित उपचार मरीज की जान बचा सकता है। हरियाणा सरकार की टेली-ईसीजी सेवा ने इस चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया है।

29 मई 2026 को मुख्यमंत्री **नायब सिंह सैनी** द्वारा शुरू की गई इस सेवा के अंतर्गत राज्य के **600 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों**—जिला अस्पताल, उप-मंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)—को जोड़ा गया है।

शुरुआती अवधि में ही **2,688 मरीजों** को इस सेवा का लाभ मिला, जबकि **131 गंभीर मरीजों** की समय रहते पहचान कर उन्हें तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि 131 परिवारों के जीवन में लौटी उम्मीद की कहानी है।

हरियाणा की टेली-ईसीजी सेवा यह सिद्ध करती है कि यदि शासन संवेदनशील हो, निर्णय समय पर लिए जाएँ और तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो स्वास्थ्य सेवाएँ केवल उपचार का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन बचाने का सशक्त अभियान बन जाती हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकती है और देशभर में डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति को नई दिशा दे सकती है।

तकनीक बनी ग्रामीण स्वास्थ्य की ताकत

टेली-ईसीजी सेवा के माध्यम से अब दूरदराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही ईसीजी जांच और विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट **सिर्फ 10 मिनट** में उपलब्ध हो रही है।

मात्र **89 रुपये** की लागत पर मिलने वाली यह सुविधा आधुनिक तकनीक को आमजन तक पहुँचाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे बड़े शहरों में अनावश्यक रेफरल कम होंगे, उपचार में देरी रुकेगी और समय रहते चिकित्सकीय निर्णय लेना संभव होगा।

डिजिटल हेल्थ की दिशा में ऐतिहासिक कदम

यह पहल केवल एक नई स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि हरियाणा की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। राज्य सरकार का लक्ष्य हृदय रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु में उल्लेखनीय कमी लाना तथा प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।

सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष **3.28 लाख से अधिक ईसीजी जांच** इस व्यवस्था के माध्यम से की जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को समय पर विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त होगा।

संवेदनशील नेतृत्व, सुरक्षित भविष्य

स्वास्थ्य मंत्री **आरती सिंह राव** का मानना है कि तकनीक तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उनका स्पष्ट संदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला नागरिक भी वही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करे, जो किसी बड़े शहर में उपलब्ध होती है।

टेली-ईसीजी सेवा इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है—जहाँ संवेदना, तकनीक और सुशासन मिलकर जनकल्याण की नई इबारत लिख रहे हैं। ■

ECLGS 5.0: संकट के समय उद्योगों का भरोसेमंद संबल, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नई शक्ति

भारत सरकार द्वारा मई 2026 में स्वीकृत **Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0** ने पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को समयबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है।

इस योजना के अंतर्गत **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को अतिरिक्त ऋण पर **100% सरकारी गारंटी** तथा अन्य पात्र व्यावसायिक क्षेत्रों को **90% गारंटी कवरेज** उपलब्ध कराया गया है। इससे बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम हुआ और वे अधिक विश्वास के साथ व्यवसायों को ऋण उपलब्ध करा सके।

योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

- पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्योगों को त्वरित कार्यशील पूंजी (Working Capital) उपलब्ध हुई।
- MSMEs की उत्पादन क्षमता एवं रोजगार संरक्षण को बल मिला।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण वितरण का जोखिम कम हुआ।
- उद्योगों में नकदी प्रवाह (Liquidity) बनाए रखते हुए आर्थिक गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित हुई।
- निर्यात, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों को आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम

ECLGS 5.0 केवल एक ऋण गारंटी योजना नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में भारत की **संवेदनशील, उत्तरदायी एवं दूरदर्शी आर्थिक नीति** का सशक्त उदाहरण है। यह पहल उद्यमियों के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान कर **विकसित भारत** के संकल्प को मजबूती देती है। ■

जयपुर मेट्रो फेज-2

विकसित राजस्थान की नई रफ्तार, आधुनिक भविष्य की मजबूत आधारशिला

राजस्थान के विकास इतिहास में 4 जुलाई 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-2 का शिलान्यास किया। लगभग **13,037 करोड़ रुपये** की यह महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने वाला आधुनिक आधारभूत ढांचा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जयपुर मेट्रो फेज-2 इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो राजधानी को अधिक सुगम, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य के अनुरूप परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगा।

41 किलोमीटर का आधुनिक कॉरिडोर, 36 स्टेशनों की नई जीवनरेखा

प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनने वाला **41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर** जयपुर के औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर पर **36 आधुनिक स्टेशन** विकसित किए जाएंगे, जिनसे लाखों नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।

यह परियोजना सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (VKI), जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को एक आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़कर राजधानी के समग्र विकास को नई दिशा देगी।



"जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है।"

— प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

ट्रैफिक से राहत, प्रदूषण में कमी और बेहतर जीवन गुणवत्ता

जयपुर मेट्रो फेज-2 के पूर्ण होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी। निजी वाहनों पर निर्भरता घटने से सड़क जाम में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।



राजस्थान के इस ऐतिहासिक विकास अभियान का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त करता है कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में प्रदेश की प्रगति, निवेश और जनसुविधाओं का नया अध्याय लिखेगी।

औद्योगिक विकास और निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन

मेट्रो नेटवर्क का विस्तार जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। इससे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निवेशकों और कर्मचारियों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे रोजगार सृजन, औद्योगिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का मजबूत मॉडल

परियोजना के माध्यम से मेट्रो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही, चाकसू एवं चौमूं जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों को मेट्रो स्टेशनों से बस सेवाओं द्वारा जोड़ने की योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी।

भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक शहर

वर्तमान में प्रतिदिन लगभग **50 हजार यात्री** जयपुर मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। फेज-2 के पूरा होने पर यह संख्या बढ़कर लगभग **2.5 लाख प्रतिदिन** तथा आने वाले वर्षों में **4 लाख से अधिक यात्रियों** तक पहुँचने का अनुमान है। यह स्पष्ट करता है कि जयपुर मेट्रो आने वाले समय में राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की मुख्य धुरी बनने जा रही है।

विकास की नई दिशा

जयपुर मेट्रो फेज-2 केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि आधुनिक राजस्थान के सपनों को साकार करने वाला परिवर्तनकारी अभियान है। यह परियोजना सुगम आवागमन, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को एक साथ आगे बढ़ाते हुए जयपुर को देश के अग्रणी स्मार्ट शहरों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ■

हरित ऊर्जा की नई उड़ानः उत्तर प्रदेश ने भविष्य की बिजली व्यवस्था की रखी मजबूत नींव

उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के बीच नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल केवल एक प्रशासनिक समझौता नहीं, बल्कि प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत आर्थिक विकास के लिए एक दूरदर्शी संकल्प है।

नई संयुक्त उद्यम कंपनी में कोल इंडिया की 51 प्रतिशत तथा यूपीआरवीयूएनएल की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इसके माध्यम से प्रदेश में ग्राउंड-माउंटेड सोलर, फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर, पवन ऊर्जा तथा पंप्ड स्टोरेज जैसी आधुनिक और विश्वस्तरीय हरित ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।

यह साझेदारी उत्तर प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पर्यावरण-अनुकूल और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, बड़े पैमाने पर निवेश और आधुनिक ऊर्जा अवसंरचना के विकास से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

कोल इंडिया की वित्तीय क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता तथा यूपीआरवीयूएनएल के विद्युत उत्पादन अनुभव का यह समन्वय उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी हरित ऊर्जा राज्यों में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

उत्तर प्रदेश की इस पहल के प्रमुख सकारात्मक आयाम

- सौर, पवन, फ्लोटिंग सोलर और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं का व्यापक विकास।
- स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा एवं बिजली आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक मजबूती।
- हरित निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर।
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश की मजबूत और दूरदर्शी पहल।

उत्तर प्रदेश का यह संयुक्त उपक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन की परियोजना नहीं, बल्कि "विकास और पर्यावरण के संतुलन" का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल आने वाले वर्षों में प्रदेश को हरित ऊर्जा, निवेश, औद्योगिक प्रगति और सतत विकास के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का आधार बनेगी। स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक कदम है। ■

यमुना जल समझौता : शेखावाटी की प्यास बुझाने वाला ऐतिहासिक संकल्प

सहकारी संघवाद की नई मिसाल नई उम्मीद, नया विश्वास

यरीब तीन दशक से लंबित यमुना जल समझौते को अंततः मूर्त रूप मिलना राजस्थान के जल इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा के संयुक्त प्रयासों से हुआ यह समझौता केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के बेहतर भविष्य की आधारशिला है। विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र के लिए यह समझौता जल सुरक्षा, सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की नई संभावनाएँ लेकर आया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न इस समझौते ने सहकारी संघवाद की उस भावना को सशक्त किया है, जिसमें राज्यों के साझा हितों को प्राथमिकता देकर जनकल्याण के बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। समझौते में वित्तीय दायित्व, जल आवंटन, संचालन, रखरखाव, पारदर्शिता और विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रूप से शामिल किया गया है, जिससे यह भविष्य के अंतरराज्यीय जल प्रबंधन के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

लगभग **34,102 करोड़ रुपये** की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत **हथिनीकुंड बैराज** से लगभग **295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन** के माध्यम से राजस्थान के हिस्से का यमुना जल चूरू जिले के **हंसियावास जलाशय** तक पहुँचाया जाएगा। इससे चूरू, सीकर, झुंझुनूं सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र में दीर्घकालिक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की भंडारण परियोजनाएँ पूर्ण होने पर सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम बताते हुए कहा कि जल केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और विकास का आधार है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस परियोजना को दोनों राज्यों के साझा सहयोग और जनहित की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

यमुना जल समझौता इस बात का प्रमाण है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक समन्वय और जनकल्याण की भावना एक साथ जुड़ती है, तब दशकों पुरानी चुनौतियाँ भी समाधान में बदल जाती हैं। आने वाले वर्षों में यह समझौता राजस्थान की जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखेगा।



यह परियोजना केवल पेयजल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ बनने वाली निरीक्षण सड़क, आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली तथा कृत्रिम जलाशय क्षेत्रीय विकास को भी गति देंगे। परियोजना के निर्माण एवं संचालन के लिए राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन इसकी प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। ■

बिहार के विकास का नया रोडमैप

नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा राज्य विकास आयोग

विकसित बिहार 2037 की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दूरदर्शी विजन



सैयद मोहम्मद अली
ब्यूरो प्रमुख (बिहार)

बिहार सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक, समावेशी और परिणामोन्मुखी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए केन्द्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर **बिहार राज्य विकास आयोग** के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री **सम्राट चौधरी** ने योजना एवं विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि यह आयोग बिहार के विकास के लिए दीर्घकालिक विजन तैयार करेगा तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, योजनाओं की प्रभावी निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।

पारदर्शिता और तकनीक से मजबूत होगी विकास प्रक्रिया

सरकार जनप्रतिनिधियों की योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों हेतु एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी, प्रगति और अनुश्रवण पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती मिलेगी।

हर जिले के लिए अलग विकास रणनीति और बजट

बिहार अब केवल योजनाएँ बनाने की दिशा में नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्थानीय विकास रणनीति और दीर्घकालिक विजन के साथ "विकसित बिहार 2037" की मजबूत नींव रखने की ओर निर्णायक कदम बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक जिले और प्रत्येक प्रखंड के लिए उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और संभावनाओं के अनुरूप अलग विकास कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही प्रत्येक जिले का अपना बजट तैयार करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि विकास योजनाएँ स्थानीय जरूरतों के अनुसार अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो सकें।

विकसित बिहार 2037 का लक्ष्य

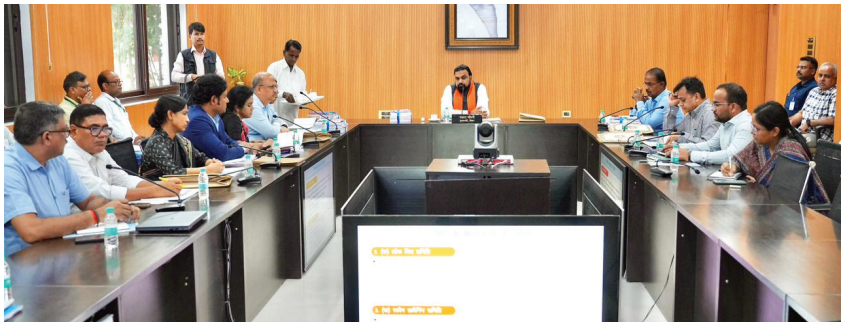
वर्ष 2037 में बिहार अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने **'विकसित बिहार 2037'** का व्यापक विजन तैयार करने का संकल्प लिया है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, बेहतर आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है।

मौसम सेवाओं का होगा डिजिटल विस्तार

कृषि और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र की सूचनाओं को सांसदों, विधायकों, जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों तक प्रतिदिन व्हाट्सएप एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से पहुँचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे समय रहते आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित होंगी और किसानों सहित आम नागरिकों को लाभ मिलेगा।

समावेशी विकास पर विशेष जोर

सरकार ने आकांक्षी जिलों सहित सभी जिलों में संतुलित विकास, योजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह पहल बिहार में सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। ■



विकास की नई राह पर उत्तर प्रदेश

विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क से आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक गौरव और निवेश को मिलेगा नया आयाम

उत्तर प्रदेश में आधुनिक और सुदृढ़ सड़क अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। यह बैठक प्रदेश को देश के सबसे सशक्त सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैठक में मथुरा–बरेली–सितारगंज, आगरा–अलीगढ़, आगरा–ग्वालियर–झांसी–नागपुर आर्थिक गलियारा, कानपुर रिंग रोड तथा नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) संपर्क मार्ग जैसी अनेक रणनीतिक परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यात्रा का समय कम होगा, माल परिवहन अधिक सुगम बनेगा तथा औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया विस्तार

राम वनगमन मार्ग, रामजानकी मार्ग एवं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जैसी परियोजनाएँ केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को सशक्त बनाने का माध्यम भी हैं। इन मार्गों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय हस्तशिल्प, व्यापार और सेवा क्षेत्र में नए अवसर विकसित होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।



742 किलोमीटर का नया विकास कॉरिडोर

शामली से गोरखपुर तक प्रस्तावित लगभग 742 किलोमीटर लंबे 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदेश के विकास का नया आधार माना जा रहा है। यह कॉरिडोर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच तेज़, सुरक्षित और आधुनिक संपर्क स्थापित करेगा। कृषि उत्पादों की आवाजाही, औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स और रोजगार सृजन के क्षेत्र में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर: संतुलित विकास की दिशा में बड़ा कदम

प्रस्तावित नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को एक उच्च क्षमता वाले सड़क नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, नए निवेश आकर्षित होंगे तथा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को गति मिलेगी।

समयबद्ध निर्माण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, उपयोगिताओं के स्थानांतरण एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा में प्रारंभ होकर समय पर पूर्ण हो सकें।

"आधुनिक सड़क अवसंरचना किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार होती है। उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा सुदृढ़ सड़क नेटवर्क निवेश, उद्योग, पर्यटन, कृषि और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करते हुए विकसित भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।"

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा।
- जेवर एयरपोर्ट संपर्क मार्ग सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति।
- राम वनगमन मार्ग, रामजानकी मार्ग एवं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा।
- शामली–गोरखपुर 742 किमी एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रदेश को नई विकास दिशा।
- नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर से औद्योगिक निवेश और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बल।
- समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश। ■

स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली की ओर ऐतिहासिक कदम

8,300 करोड़ की मेगा परियोजना से राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी नई दिशा

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार और विश्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा ₹स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली₹ (Delhi Clean Air Program) के शुभारंभ के साथ राजधानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। सात वर्षों (सितंबर 2026–अगस्त 2033) तक संचालित होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ है, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहयोग विश्व बैंक द्वारा तथा 35 प्रतिशत योगदान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होगा प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण

यह परियोजना आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक विश्लेषण और डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली पर आधारित होगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना की जाएगी। इससे प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर केंद्रित होगी कार्ययोजना



परियोजना के दूसरे प्रमुख स्तंभ के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर सीधे नियंत्रण की रणनीति अपनाई जाएगी। पुराने एवं अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने, सार्वजनिक परिवहन को अधिक सशक्त बनाने, निर्माण स्थलों एवं सड़कों की धूल पर नियंत्रण तथा ठोस कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि स्वच्छ वायु केवल पर्यावरण विभाग का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक विभाग, संस्था और नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार समन्वित प्रयासों, आधुनिक तकनीक और जनसहभागिता के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई उम्मीद, नई दिशा

विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ यह परियोजना केवल प्रदूषण नियंत्रण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने का दीर्घकालिक संकल्प है। यदि निर्धारित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो दिल्ली स्वच्छ वायु, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत शहरी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है। ■



विकसित भारत की राह पर राजस्थान

गांवों की नई तस्वीर गढ़ने का संकल्प, विकास मॉडल बनने की ओर अग्रसर प्रदेश



नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में राजस्थान ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी सोच और प्रभावी कार्ययोजना का सशक्त परिचय दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिव राज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के कृषि, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य की उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य की विकास रणनीति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ₹विकसित भारत–विकसित ग्राम₹ के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है, और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ग्रामीण आधारभूत ढांचे, आजीविका, कृषि, जल संरक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रभावी कार्य कर रही है।

सम्मेलन में राजस्थान द्वारा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को राष्ट्रीय मंच पर साझा किया गया। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

राजस्थान की सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश दिया कि राज्य केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि नवाचार, सुशासन और जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास का एक प्रेरणादायी मॉडल स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित गांवों के निर्माण का यही संकल्प आने वाले समय में विकसित भारत की मजबूत आधारशिला सिद्ध होगा। ■

माइंस से माइंड्स तक
झारखंड के विज़न 2050 की नई उड़ान





झारखंड सरकार ने राज्य के विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय **नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन** के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाला झारखंड केवल खनिज संपदा का नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और तकनीक का भी अग्रणी केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री **हेमन्त सोरेन** ने अपने संबोधन में कहा कि "झारखंड की पहचान केवल माइंस से नहीं, बल्कि माइंड्स से भी होनी चाहिए।" यह विचार राज्य की विकास यात्रा को पारंपरिक संसाधनों से आगे बढ़ाकर ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का सशक्त संकल्प है।

इस महत्वपूर्ण विचार-विमर्श में सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लेकर **झारखंड के विज़न 2050** को आकार देने के लिए अपने सुझाव दिए। विशेष रूप से **Microsoft, Google** और **IBM** जैसे वैश्विक तकनीकी संस्थानों की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि झारखंड भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है।

कार्यक्रम के दौरान **झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशंस** तथा **पीपीपी पॉलिसी** के कॉन्सेप्ट पेपर प्रस्तुत किए गए। इन नीतियों पर उद्योग जगत एवं विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित कर सरकार ने सहभागी एवं पारदर्शी नीति-निर्माण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया।

बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद के माध्यम से निवेश, नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल अवसंरचना और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यह पहल झारखंड में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

मुख्यमंत्री का यह दृष्टिकोण कि "**प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को समान महत्व दिया जाए**" राज्य के समावेशी, सतत एवं तकनीक-संचालित विकास की मजबूत आधारशिला है। यह पहल केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि झारखंड को "**रिसोर्स स्टेट**" से "**नॉलेज स्टेट**" बनाने की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है।

यह कंसल्टेशन झारखंड के लिए केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार, निवेश, रोजगार और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यदि इन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में झारखंड देश के अग्रणी डिजिटल एवं औद्योगिक राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकता है। ■

वेलमैन फाउंडेशन: सेवा, संस्कार और स्वावलंबन का सशक्त अभियान

गरीबों के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगा रहा है ग्रेटर नोएडा का वेलमैन फाउंडेशन

आज जब समाज को संवेदनशील नेतृत्व और जनहित के प्रति समर्पित संस्थाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, ऐसे समय में **वेलमैन फाउंडेशन** उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा, शिक्षा और स्वावलंबन का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। वर्ष 2019 से सामाजिक परिवर्तन की इस यात्रा ने हजारों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संचार किया है।

शिक्षा से सशक्त भविष्य की ओर

फाउंडेशन ने अपनी शुरुआत वंचित बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों से की। साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और विशेष रूप से महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। इन प्रयासों ने शिक्षा के साथ सामाजिक चेतना को भी नई दिशा दी।

कोविड संकट में बना हजारों परिवारों का सहारा

कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब अनेक परिवार आजीविका और भोजन के संकट से जूझ रहे थे, तब वेलमैन फाउंडेशन ने मानवता का परिचय देते हुए **ग्रेटर नोएडा** और **मिर्जापुर** में लगभग **5,000 जरूरतमंद** लोगों तक राशन सामग्री पहुँचाई। इस पहल ने केवल भूख मिटाने का कार्य नहीं किया, बल्कि समाज में विश्वास,



सहयोग और मानवीय संवेदना की मिसाल भी कायम की।

कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की नई उड़ान

फाउंडेशन का सबसे प्रभावशाली कार्य महिलाओं और युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। सिलाई-प्रशिक्षण, बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से **1,500 से अधिक प्रतिभागियों** को प्रमाणित प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। अनेक महिलाएँ आज घरेलू उद्योग संचालित कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं, जबकि युवा डिजिटल कौशल के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण बना परिवर्तन का आधार

वेलमैन फाउंडेशन का मानना है कि यदि महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। इसी सोच के साथ संस्था स्वास्थ्य जागरूकता, मासिक धर्म स्वच्छता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आत्मविश्वास निर्माण पर निरंतर कार्य कर रही है। इन पहलों ने महिलाओं को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है।

ग्रेटर नोएडा में कौशल विकास का नया केंद्र

वर्ष 2025 में सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना संस्था की दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। यह केंद्र युवाओं और महिलाओं को बाज़ार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाने का कार्य कर रहा है।

सीएसआर के माध्यम से सामाजिक विकास का मजबूत मॉडल

वेलमैन फाउंडेशन विभिन्न **कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR)** पहलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों









में प्रभावी कार्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्था का उद्देश्य उद्योग जगत और समाज के बीच साझेदारी स्थापित कर सतत एवं समावेशी विकास को गति देना है।

समाज परिवर्तन का विश्वसनीय नाम

सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्यरत वेलमैन फाउंडेशन आज केवल एक संस्था नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के विश्वास का प्रतीक बन चुका है। शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और मानवीय सहायता के माध्यम से यह संगठन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाने का सतत प्रयास कर रहा है। आने वाले वर्षों में संस्था का लक्ष्य अपने कार्यक्रमों का विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। ■

भारत की नई डिजिटल उड़ान

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत

भारत अब केवल मोबाइल फोन का विशाल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि विश्व का अग्रणी **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल निर्माण** केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी लक्ष्य को नई गति देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS)** को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, घरेलू वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करने,





मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) केवल एक औद्योगिक योजना नहीं, बल्कि रोजगार, नवाचार, निवेश और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी कदम है। यह पहल भारत को 'मेक इन इंडिया' से 'मेड बाय इंडिया, फॉर द वर्ल्ड' की नई पहचान दिलाते हुए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी।

आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को सशक्त बनाने तथा भारतीय मोबाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

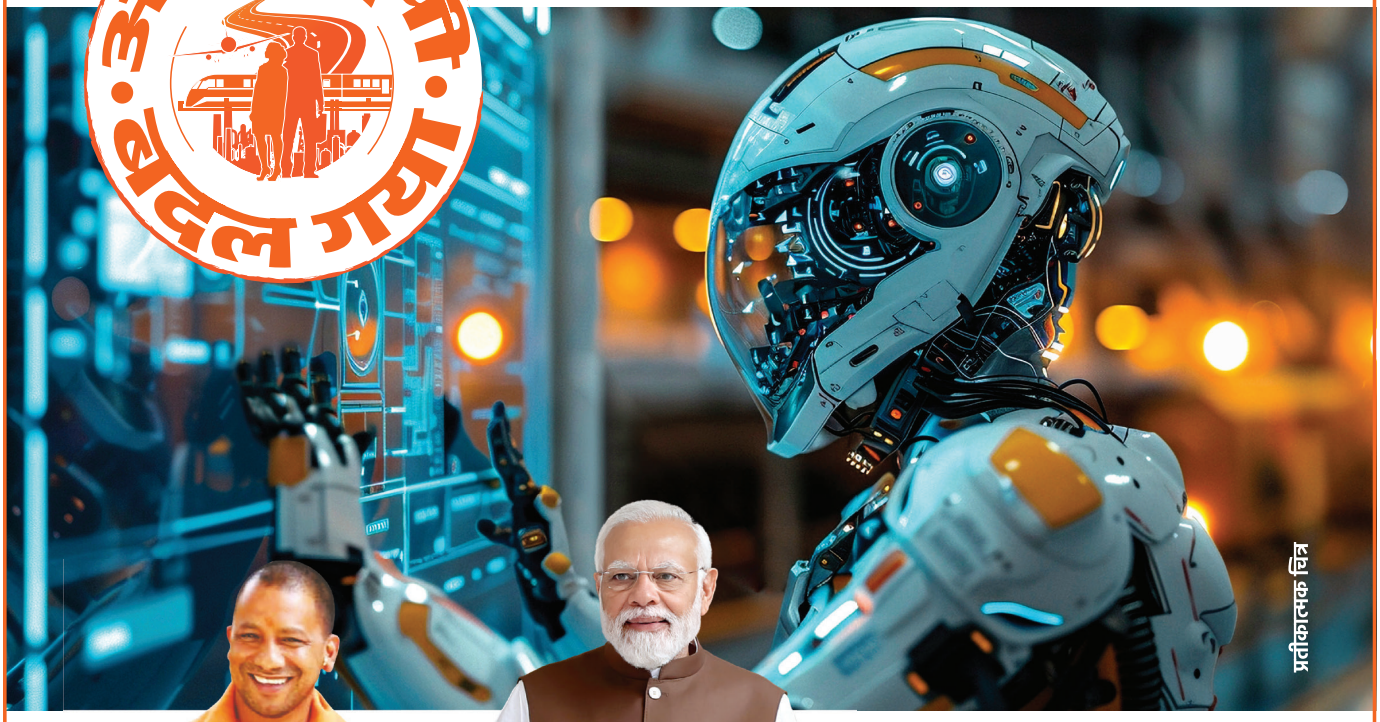
यह योजना देश में मोबाइल निर्माण से जुड़े उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी तथा 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को और अधिक मजबूती मिलेगी। भारतीय कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक निवेशकों के लिए भी भारत एक विश्वसनीय एवं आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

मोबाइल निर्माण क्षेत्र के विस्तार से लाखों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अनुसंधान, नवाचार, डिजाइन, सेमीकंडक्टर, कंपोनेंट निर्माण और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को भी नई गति मिलेगी। इससे देश में उच्च कौशल आधारित रोजगार बढ़ेंगे और तकनीकी दक्ष मानव संसाधन तैयार होगा।

एमपीएमएस के माध्यम से भारत की वैश्विक निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, प्रतिस्पर्धी लागत और मजबूत आपूर्ति तंत्र के बल पर भारतीय मोबाइल विश्व के अनेक देशों में अपनी मजबूत पहचान बनाएंगे। यह पहल भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय भागीदार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ■

पहले तकनीक में लाचार
आज हर ओर नवाचार

अपना यूपी बदल गया



प्रतीकात्मक चित्र



2017 से पहले आईटी और प्रौद्योगिकी में दूरदर्शी सोच का अभाव

2026 में डेटा और AI हब, 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक पार्क, उत्तर प्रदेश AI मिशन की शुरुआत

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

SARDAR PATEL POST GRADUATE INSTITUTE OF DENTAL & MEDICAL SCIENCES

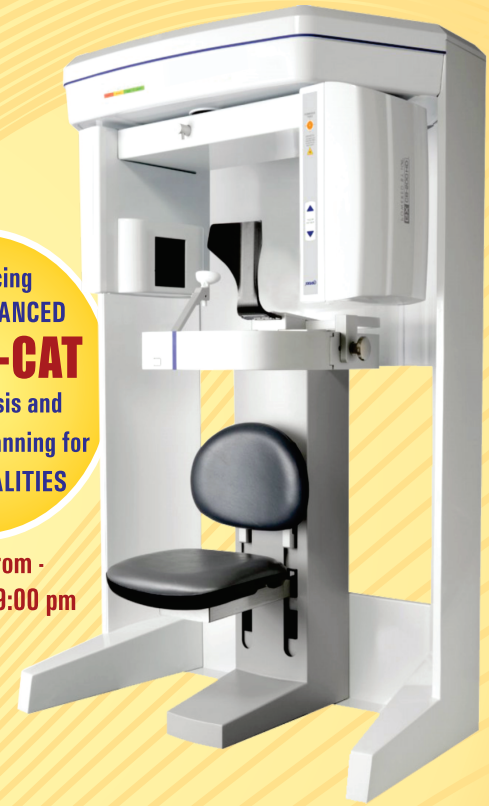
(Recognized By Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India and Dental Council of India, New Delhi)

COURSES OFFERED :

- B.D.S.
- M.D.S. (ALL SPECIALITIES)
- DIPLOMA IN IMPLANTOLOGY
- PARA DENTAL COURSES
- DENTAL HYGIENIST
- DENTAL MECHANIC

FACILITIES OFFERED :

- SEMINAR ROOM, LIBRARY & MUSEUMS
- LABORATORY & COMPUTER LAB
- Wi-Fi ENABLED CAMPUS
- AUDITORIUM/CONFERENCE HALL
- HOSTELS & TRANSPORTATION
- SPORTS COMPLEX
- CAFETARIA, CAFE COFFEE DAY
- HOSPITAL



introducing MOST ADVANCED **CBCT i-CAT** for Diagnosis and Treatment Planning for ALL SPECIALITIES

- Open From -
9:00 am to 9:00 pm



"ADVANCED DENTISTRY AT ACADEMIC LEVEL"

"CHAUDHARY VIHAR" SARDAR PATEL CHOWK, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226025

0522-2442030-35, 9451188900, 99194 36362